# स्वदेशी पत्रिका

वर्ष–24, अंक–3
फाल्गुन–चैत्र 2072, मार्च 2016

*संपादक*
**विक्रम उपाध्याय**

*पृष्ठ सज्जा एवं टंकन*
**सुदामा दीक्षित**

*कार्यालय*
**धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022**
से प्रकाशित
दूरभाष : 011–26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

# अ नु क्र म

**पाठकनामा/उन्होंने कहा 4**
**समाचार परिक्रमा 34-37**

कवर तृतीय पेज 39
कवर चतुर्थ पेज 40

**आवरण कथा** – पृष्ठ–6

**किसानों में विश्वास का बजट**

**विक्रम उपाध्याय**

1 कवर पेज
2 कवर द्वितीय पेज

09 **आवरण कथा–2**
संतुलित विकास पर फोकस
.......... **डॉ. अश्वनी महाजन**

11 **आवरण कथा–3**
बजट 2016: जरूरी है किसानों की आय बढ़ाना
.......... **देविंदर शर्मा**

13 **आर्थिक चिंतन–1**
बचत को प्रोत्साहित करने की दरकार
.......... **शिवाजी सरकार**

16 **आर्थिक चिंतन–2**
अर्थव्यवस्था को गति देने के उपाय
.......... **डॉ. भरत झुनझुनवाला**

18 **आर्थिक चिंतन–3**
युवा सपनों का बजट
.......... **डॉ. सुभाष शर्मा**

20 **काल गणना**
भारतीय काल गणना की सार्वभौमिकता व खगोल शुद्धता
.......... **प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा**

24 **मुद्दा**
देश की अखंडता को चुनौती
.......... **निरंकार सिंह**

27 **मुद्दा–2**
भारत विरोध का बनता केंद्र, जेएनयू
.......... **संजय द्विवेदी**

30 **जल**
नदियां जुड़ेगी तो धारा मुड़ेगी
.......... **धर्मेन्द्र भदौरिया**

32 **विमर्श**
आरक्षण से किसको, कितना लाभ!
.......... **मनोज भारत**

# पाठकनामा

## किसान कब बनेंगे आत्मनिर्भर?

वैसे तो बजट में किसानों को लेकर खूब सारे दावे किए गए हैं। कहा गया है कि अगले 5 सालों में किसानों की आय दुगनी हो जायेगी। अभी एक सामान्य किसान की आय 2000 से 4000 रू. प्रति माह की है। अगर 5 साल में यह आय दुगनी हो भी जाती है तो इससे कितना फर्क पड़ेगा। खेती पर आवश्यकता से अधिक निर्भरता जब तक बनी रहेगी, तब तक आय में मामूली अंतर से किसानों का कुछ भला नहीं होने वाला। जरूरत है किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की। बैशाखी के सहारे किसान जब तक रहेंगे, तब तक वे दीन हीन बने रहेंगे। जब तक खेती एक लाभदायक पेशा या व्यवसाय नहीं बनती, तब तक किसी बड़े परिवर्तन की अपेक्षा नहीं की जा सकती। मॉडल ऐसा होना चाहिए कि किसानों को खेती के साथ कुटीर उद्योग से भी जोड़ा जाए। ताकि उन्हें वर्ष भर रोजगार मिल सके, तभी किसान आत्मनिर्भर बन पायेंगे।

**सुनील तिवारी,** *शाहदरा, दिल्ली*

✽✽✽✽✽

## बजट से उम्मीद तो बंधी!

आजादी के बाद दूसरा या तीसरा मौका है जब किसी सरकार ने कॉरपोरेट और उद्योग से ज्यादा किसानों और ग्रामीणों को बजट में महत्व दिया है। प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना और इस बजट में सिंचाई की सुविधा के लिए 17000 करोड़ रूपये का प्रावधान, यह उम्मीद तो जगाता ही है कि आने वाले दिनों में ग्रामीण भारत की दशा बदलने वाली है। बजट में सिर्फ कृषि क्षेत्र को ही अतिरिक्त धन नहीं मिला है, बल्कि ग्रामीण विकास के लिए मोदी सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। ग्रामीण सड़क योजना के लिए 19000 करोड़ का प्रावधान अन्ततः ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर को बढ़ावा देगा। गांवों की आमदनी बढ़ेगी तो इसका सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। बाजार में मांग बढ़ेगी और उद्योग धंधे चल निकलेगें। उम्मीद है कि यह बजट देश को आर्थिक मंदी से निकालकर विकास के रास्ते पर डाल देगा।

**सचिन चौधरी,** *झारखंड*

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

**संपादकीय कार्यालय**

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेल : swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए

आजीवन सदस्यता शुल्कः 15,00 रुपए

यदि शुल्क भेजने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740

IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

## उन्होंने कहा

कुछ लोगों की उम्र बढ़ जाती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती।

**नरेन्द्र मोदी**
लोकसभा में

देश को पहली और इकलौती महिला प्रधानमंत्री देने पर कांग्रेस को गर्व है।

**सोनिया गांधी**
महिला दिवस पर

आतंकवाद पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन इशरत जहां केस की जांच में फ्लिप फ्लॉप हुआ।

**राजनाथ सिंह**
लोकसभा में

जिस दिन राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के १/१० भी हो जायेंगे, उस दिन मेरा वोट उनको जायेगा। तब तक प्रधानमंत्री को काम करने दीजिए।

**अनुपम खेर**
टेलिग्राफ डिबेट

जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो, ठीक उसी समय पर उसे करना ही चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है।

**अनमोल वचन**

सं
पा
द
की
य

# बैंकों के साथ ज्यादती क्यों?

अभी तक हम वैश्विक मंदी से इसलिए बचते आयें हैं क्योंकि हमारे बैंक और वित्तीय संस्थान काफी मजबूत रहे हैं। जब भी विदेशी निवेशकों की बिकवाली जोर पकड़ती थी और भारत के शेयर बाजार ध्वस्त होने की कगार पर होते थे तो हमारे बैंक और वित्तीय संस्थान आगे आकर उन्हें संभाल लेते थे। लेकिन अब ये बचाव की बजाए खुद ही बीमार हो गये हैं। आशंका यह जताई जा रही है कि जल्द ही यदि डूबते बैंकों को सहारा नहीं दिया गया तो कई बैंक कंगाली के शिकार हो जायेंगे। इससे न सिर्फ हमारे वित्तीय संस्थाओं के ढ़ांचे पर असर पड़ेगा बल्कि भारत की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हो जायेंगे। 2008 में जब अमरीका में लिमेन डूबा था तब भी यह सवाल खड़ा हुआ था कि क्या भारतीय बैंक कहीं इस तरह के खतरे के दायरे में तो नहीं। लेकिन तब हमारे बैंकों की वित्तीय स्थिति और उनका कारोबार इतना मजबूत था कि लिमेन की आंधी से हम पूरी तरह बचे रहें। लेकिन पिछले 5 सालों में हमारे बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान अनियमियताओं के शिकार होते चले आ रहे हैं। हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि बैंकों की गैर निस्पादित संपत्तियां (एनपीए) 5 लाख करोड़ रूपये से भी ऊपर पहुंच गई है। हालांकि इस आंकड़े को लेकर अभी भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कहा जा रहा है कि वास्तविक एनपीए इससे कहीं बहुत ज्यादा अधिक है। अकेले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 11 लाख करोड़ की पूंजी डूबती हुई नजर आ रही है। इलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और सिंडिकेट बैंक के हालात तो बहुत ज्यादा खराब है। बजट में वित्तमंत्री ने बैंकों की सहायता के लिए 25 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। लेकिन सबको मालूम है कि इतनी राशि से बैंकों की स्थिति सुधरने वाली नहीं। लिहाजा सरकार में भी बैंकों को लेकर घोर माथापच्ची चल रही है। कई विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। उनमें प्रमुख रूप से बैंकों का एक–दूसरे में विलय और बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी 51 फीसदी तक सीमित करने का विचार है। मौजूदा हालत में इन दोनों ही विकल्पों को आजमाना आसान नहीं है। बैंकों के आपस में विलय से पहले कर्मचारियों और शेयरधारकों की मंजूरी एक टेढ़ी खीर साबित होगी। इसके अतिरिक्त बीमार बैंकों की विनिवेश योजना भी सिरे चढ़ती दिखाई नहीं दे रही। बाजार की मौजूदा स्थिति ऐसी नहीं कि बैंकों के शेयर उचित मूल्य पर आसानी से बिक सके। सरकार के लिए बेहतर यही होगा कि बैंकों के प्रबंधन में पेशेवर लोगों को शामिल कर एनपीए को कम करने के साथ–साथ डूब रही पूंजी को भी निकालने के प्रयास किए जाएं। यह कोशिश रहे कि किंगफिशर जैसे लोन लूट भविष्य में न हों, क्योंकि पीछे राजनीतिक दबाव डालकर उलूल–जुलूल तरीके से ऋण बांटे गये। यह समझ में नहीं आता कि आज सीबीई और परवर्तन निदेशालय यह निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि किंगफिशर को लोन देने में तमाम अनियमितताएं बरती गई लेकिन तब बैंक के ऑडिटर और रिजर्व बैंक के अधिकारी क्यों चुप रहें। जाहिर है कि राजनीतिक दबाव के चलते बैंकों ने गलत काम करके भी चुप्पी साधे रखी। अब जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लिया है और बैंकों को लोन रिकवरी के लिए हर संभव प्रयास करने को कहा है। जब जाकर यह अफरा–तफरी मची है। एक तरफ छोटे ऋण लेने वाले पर बैंक वसूली के लिए ज्यादती करते रहे हैं, दूसरी तरफ रसूखदारों को लोन देने में अपने उपर की ज्यादती सहते रहे हैं। कहने को हमारे बैंक और वित्तीय संस्थान स्वायत्त है लेकिन हाल के घोटालों और पहाड़ जैसी एनपीए की स्थिति देखते हुए कहा जा सकता है कि या तो बैंकों का प्रबंधन पेशेवर नहीं है या फिर लालच या दबाव में काम कर रहा है। बैंक हमारे वित्तीय बाजार के प्राण तत्व हैं। न यह सिर्फ हमारी जमा या बजट सुरक्षित रखने के प्रति उत्तरदायी है बल्कि हमारे व्यवसाय और उद्योग के लिए सहायक अवयव भी है। प्रधानमंत्री मोदी की तमाम जन योजनाओं की सफलता इन्हीं बैंकों के कामकाज पर आश्रित है। यहीं नहीं ये हमारी अर्थव्यवस्था की सही तस्वीर भी पेश करते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार की बहुत गुंजाइश है। आवश्यकता है कि इसे तमाम दबावों से मुक्त रखकर स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम बनाया जाए और देश के विकास में इसकी भूमिका को देखते हुए इसे और सशक्त बनाया जाए। हालांकि इस तथ्य से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि पिछले कुछ सालों में वैश्विक बाजार संकुचित हुआ है, कारोबार कम हुए हैं, कॉरपोरेट की बैलेंस शीट भी खराब हुई है और उसका असर बैंक के कारोबार पर भी पड़ा है। फिर भी हमारे बैंक कम से कम जोखिम लेकर काम करने के आदी है और उनकी यह खूबी उनकी बैलेंस शीट में भी दिखनी चाहिए। ❑

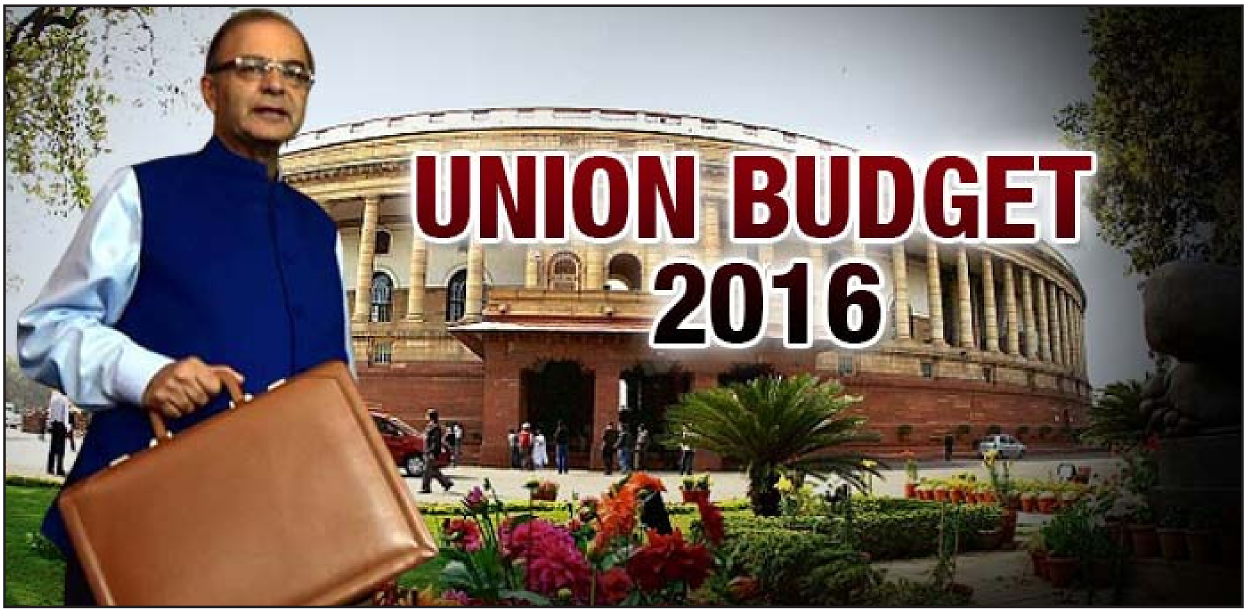


# किसानों में विश्वास का बजट

*अभी हमारी कषि का आकार लगभग 20 लाख करोड़ का है और जीडीपी में कषि का योगदान 18 फीसदी का है। यदि कषि और किसानों को यह बजट रास आया तो अगले पांच साल में कषि बाजार का आकार 40 लाख करोड़ और जीडीपी में कषि का योगदान 30 फीसदी तक हो सकता है*

– **विक्रम उपाध्याय**

**हारे–थके** गिनती के कॉरपोरेट को उपहार देकर देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के बजाय करोड़ों किसानों और लाखों छोटे उद्योगों को सहारा देकर देश को आगे बढ़ाया जाए, इस बजट के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने यही संदेश दिया है। अरुण जेटली ने वित्तमंत्री के नाते प्रधानमंत्री की राजनीतिक सोंच और उनके विजन को बखूबी बजट में उतारा है। सूट–बूट की सरकार का जबरन तमगा देने वाले और किसानों की उपेक्षा करने के आरोप लगाने वालों के लिए वर्ष 2016–17 का बजट माकूल जवाब लेकर आया है। यदि सचमुंच पांच साल में किसानों की आय दुगनी हो गई तो हमारी अर्थव्यवस्था का कायापलट ही हो जाएगा। अभी हमारी कृषि का आकार लगभग 20 लाख करोड़ का है और जीडीपी में कृषि का योगदान 18 फीसदी का है। यदि कृषि और किसानों को यह बजट रास आया तो अगले पांच साल में कृषि बाजार का आकार 40 लाख करोड़ और जीडीपी में कृषि का योगदान 30 फीसदी तक हो सकता है जो कि 1990–91 में 32 फीसदी था।

वैसे सेवा क्षेत्र व उद्योग का सहयोग जीडीपी में ज्यादा है, लेकिन इन दोनों क्षेत्रों पर कृषि के मुकाबले जन निर्भरता काफी कम हैं। एक कृषि ही है जहां आज भी आधी से ज्यादा जनसंख्या निर्भर है। आधी आबादी को खाने–पीने के दैनिक संघर्ष से बाहर निकाल दिया तभी देश विकासशील का तमगा छोड़कर विकसित देश की पहचान बना सकेगा। वर्ना हम अमीरों को अमीरों और गरीबों को और गरीब बनाते जायेंगे। ऐसा नहीं कि भारतीय कृषि में विकास की संभावनाएं नहीं है। हम दुनिया के सबसे बड़े अनाज उत्पादक देश हैं। डेयरी उद्योग में भी हमारा जवाब नहीं। लेकिन तिलहन–दलहन के साथ–साथ सब्जियों और फलों में हमसे चीन मिलों आगे हैं। जबकि खेती लायक जमीन हमारे पास सबसे ज्यादा है। भारत के पास 1573 लाख हेक्टेयर भूमि खेती के लायक है। हमारी कुल भूमि का 60 फीसदी हिस्से पर खेती हो सकती है, जबकि चीन के पास उसकी कुल भूमि का 34 हिस्से पर ही कृषि कार्य होता है। लेकिन हमारी कृषि मानसून पर निर्भर होने के कारण चीन के मुकाबले हमारा

उत्पादन कम है। यही बात बजट भाषण में अरुण जेटली ने भी दोहराई। इसलिए इस बजट में कोशिश यह है कि सिचाई की सुविधाओं में गुणात्मक वृद्धि की जाए। बड़ी–बड़ी नहरों के साथ गांव ज्वार के पांच लाख तालाबों और अन्य जल स्रोतों को भी दुरूस्त किया जाए। बकौल वित्तमंत्री बजटीय सहायता के जरिए 28.5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधाओं से युक्त किया जाएगा और पांच लाख एकड़ भूमि पर ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।

अगले वित्त वर्ष के लिए बजट में कृषि के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, उनमें किसानों के कल्याण के लिए 35,984 करोड़ और 60 हजार करोड़ रुपये की लागत से सूखा प्रभावित इलाकों में वाटर रिचार्ज और कलस्टर डेवलपमेंट को मजबूती दी जाएगी। इतना नहीं 9 लाख करोड़ रुपये तक कृषि कर्ज की सुविधाएं उपलब्ध होगी तो मृदा जांच और प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए भी 5000 करोड़ रुपये से अधिक के प्रावधान रखे जाएंगे। यूपीए के शासनकाल में शुरू की गई कई सिंचाई परियोजनायें पैसे न होने के कारण अधर में लटकी हुई हैं। उनके लिए धन जुटाने की जिम्मेदारी नाबार्ड को दी गई है। नाबार्ड 20 करोड़ रुपये का एक विशेष डेडिकेटेड इरीगेशन फंड स्थापित करेगा। जिसके जरिए विभिन्न राज्यों में चल रही सिचाईं परियोजनाओं का वित पोषण किया जाएगा। यह कहना ठीक नहीं कि वित्तमंत्री ने कृषि के लिए ही सिर्फ अतिरिक्त वित्त की व्यवस्था की है। बल्कि इस बजट के जरिए कृषि और ग्रामीण विकास दोनों को एक सूत्र में पिरो दिया गया है।

खेती के साथ–साथ ग्रामीण ढांचागत विकास को भी बड़े पैमाने पर गति देने की कोशिश की गई है। ग्रामीण सड़क निर्माण के लिए 19,000 करोड़ का प्रावधान मायने रखता है। कुल

## हमें क्या मिला?

ट्रेन में हो या बाजार में या किसी बैठक या चर्चा में हर कोई पूछ रहा है हमें क्या मिला इस बजट में।

***यदि आप एक मध्य आय वर्ग के सामान्य नागरिक हैं:*** इस बजट में एक आम नागरिक के लिए बाहर से लाभ दिखने वाला कुछ भी नहीं है। सीधे फायदा के बजाय सेवा कर में बढ़ोतरी के कारण कुछ नुकसान ही दिखता है। आय कर सीमा में कोई बढ़ोतरी हुई नहीं और ना ही इस्तेमाल की चीजों के दाम कम हुए। पर जरा बजट को ध्यान से पढिए और समझिए। इस बजट में आपके लिए भी बहुत कुछ है। पहले कर बचाने के लिए आपको वित्तमंत्री ने तीन बड़े अवसर दिए हैं। एक तो तीन हजार रुपये की सीधी छूट। यदि घर खरीदने की सोंच रहे हैं तो 50 हजार रुपये की अतिरिक्त ब्याज में कर छूट और यदि किराए पर रह रहे तो 60 हजार तक के किराए खर्चे पर भी कर छूट। पर जनाब सिर्फ करों में छूट पर मत जाइए। इस बजट में आपके लिए छूट के आगे भी कुछ है।

***यदि आप स्टार्टअप इंडिया से जुड़ना चाहते हैं*** तो कई एजेंसियां आपका हाथ थामने के लिए तैयार हैं। यदि आप किसी नये आईडिया के साथ काम करने के लिए एक अप्रैल 2016 के बाद कोई कंपनी बनाकर व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो कॉरपोरेट कर में पांच फीसदी की छूट प्राप्त हैं। यदि आप दो करोड़ रुपये तक का कोई टर्नओवर वाला व्यवासाय करते हैं तो सिर्फ 8 फीसदी कर देकर आयकर विभाग के किसी भी चक्कर से बच सकते हैं।

***यदि आप महिला, अनुसूचित जाति या जनजाति के अन्तर्गत आते हैं*** तो इस बजट ने अवसर के बहुत सारे दरवाजे खोल दिए हैं। बैंक के हर ब्रांच में स्टैंडअप इंडिया योजना के तहत आपको वित्तीय सुविधा मुहैया कराने के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह राशि मुद्रा बैंक से जारी सहायता से अलग है। वैसे मुद्रा बैंक चालू वर्ष में ही लाभार्थियों को एक लाख करोड़ रुपये तक की सहायता बांट चुका है। ट्रेनिंग एवं उद्योग लगाने के लिए सलाहकार सेवाएं भी मुफ्त मिलने वाली है। यही नहीं आपके लिए पूंजी अभिवृद्धि कर में छूट प्रदान की गई हैं और आयकर से भी छूट प्राप्त होने वाली है।

***यदि आप पेशेवर हैं और आयकर विभाग द्वारा सूचीबद्ध किसी पेशे के अंतर्गत आते हैं*** तो आपके लिए इस बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। यदि आप पचास लाख रुपये तक पेशेवर सुविधाओं की फीस प्राप्त करते हैं तो आपको एक अनुमानित कर यानी आठ फीसदी देकर ही छुट्टी पा लेनी हैं। वित्तमंत्री ने इसे प्रिजम्पटिव टैक्स रिजिम का नाम दिया है। अब आपको अपने पेशे से जुड़े किसी कागजात को सुरक्षित रखने या लेखा–जोखा का हिसाब रखने की जरूरत नहीं है। यदि आप पचास लाख तक की फीस वसूल करते हैं तो अपनी आय पर आठ फीसदी के बराबर कर दीजिए और मजे कीजिए। ❑

## आम बजट 2016 के मुख्य बिंदु

- अमीरों पर सरचार्ज 12 से बढ़ाकर 15 फीसदी
- बीड़ी के अलावा बाकी सभी तंबाकू उत्पादों पर 10–15 फीसदी टैक्स बढ़ा
- सोने के आयात पर एक्साइज ड्यूटी 1 फीसदी बढ़ी
- 1 करोड़ से ज्यादा आय वालों पर सरचार्ज बढ़ा
- 35 लाख के होम लोन पर 50 हजार की छूट
- पहली बार मकान खरीदने वालों को टैक्स में छूट
- हाउस रेंट अलाउंस 24 हजार से बढ़ाकर 60 हजार करने का प्रावधान
- इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं
- पांच लाख की आमदनी पर 3 हजार टैक्स का फायदा
- किराए के मकानों में रहने वाले व्यक्तियों को राहत, 60 हजार की छूट
- बिना किसी लीक के गरीबों तक पहुंचेगी पब्लिक मनी
- डाकघरों में ATM की सुविधा देने की कोशिश होगी
- एक दिन में होगा कंपनियों का रजिस्ट्रेशन
- लंबित सिंचाई परियोजनाओं पर मिशन मोड में आगे बढ़ना वक्त की जरूरत
- 160 हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा
- गांवों के लिए डिजिटल साक्षरता मिशन
- हाइवे के लिए 55 हजार करोड़ रुपये
- EPF के लिए 1000 करोड़ का फंड देगी सरकार
- नए कर्मचारियों के PF का हिस्सा तीन साल तक सरकार देगी
- उच्च शिक्षा में मदद के लिए 1000 करोड़ रुपये
- स्टैंड अप इंडिया के तहत SC&ST के लिए खास योजनाएं
- दो साल में 62 नए नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे
- विश्वस्तरीय होगा शिक्षा का स्तर, शुरुआती 1000 करोड़ रुपये की मदद से उच्च शिक्षा एजेंसी की स्थापना की जाएगी
- 1500 स्किल डेवलपमेंट सेंटर खुलेंगे, 17000 करोड़ रुपये दिए गए
- राष्ट्रीय डायलिसिस सेवा की शुरुआत
- सस्ती दवा के लिए देश भर में 30 हजार स्टोर खुलेंगे
- गरीबों को रसोई गैस के लिए 200 करोड़ रुपये
- ग्रामीण विकास– ग्राम पंचायतों को प्रति पंचायत 80 लाख रुपये अनुदान
- किसानों को बकाया कर्ज पर ब्याज के बोझ से बचाने के लिए 15,000 करोड़ का आवंटन
- 89 सिंचाई परियोजनाएं फास्ट ट्रैक मोड में
- नया सुधार फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन का आधुनिकीकरण, कंपोस्ट की बिक्री
- 1 मई 2018 तक सभी गांवों में बिजली की योजना
- गावों में बिजली के लिए 8500 करोड़ रुपये
- मनरेगा के लिए 30500 करोड़ रुपये
- बीपीएल परिवारों तक पहुंचेगी एलपीजी
- प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए 19 हजार करोड़ रुपये
- दालों के उत्पादन के लिए 500 करोड़
- 6000 करोड़ भूजल संसाधन के लिए
- पांच लाख एकड़ में जैविक खेती
- सिंचाई योजना के लिए 17000 करोड़ की रकम
- 5 साल में किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य ❑❑

मिलाकर ग्रामीण विकास के लिए 87,775 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं के लिए भी दो लाख 87 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। गांवों में रोजगार और मिले और बाजार में मांग बढ़े इसके लिए मनरेगा का बजट भी इस वर्ष 4000 करोड़ रुपये बढ़ाकर 38,500 करोड़ कर दिया गया हैं। हर ब्लॉक में किसानों को सूखे या अन्य विपदाओं से तत्काल राहत देने के लिए दीनदयाल अंतोदय मिशन की स्थापना की गई है। मई 2018 तक सभी गांवों को बिजली पहुंचा देने की लक्ष्य भी इस बजट में तय किया गया है।

**सरकार ने पहली बार किसानों, ग्रामीणों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर एक साथ इतना खर्च करने का साहस किया है।**

कुछ लोग यह जायज सवाल उठा रहे हैं कि इन बजटीय प्रावधानों से क्या सचमुच किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। क्या किसानों को खेती से नियमित रोजगार मिल जाएगा और जितनी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है उनका ठीक से लालन–पालन हो जाएगा। ये सवालों के पीछे ठोस कारण भी हैं। गुजरात, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे ही कुछ राज्य हैं, जहां कृषि विकास दर 10 फीसदी तक पहुंची है। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विकास दर 2 से 3 फीसदी ही रही है। ऐसा पांच साल में क्या हो जाएगा कि पूरे देश की खेती की विकास दर 10 फीसदी से अधिक पहुंच जाएगी? सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि किसानों की आय इस समय औसत 2000 रुपये महीने भी नहीं है। यदि दो हजार के मुकाबले 4000 रुपये की आय पांच साल बाद हो भी जाती है तो आने वाले दिनों में मुद्रास्फीति में जो बढ़ोतरी होगी, उसके अनुपात में वास्तविक आय कितनी बढ़ पाएगी। कुछ लोग यह प्रश्न भी उठा रहे हैं कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए फसलों की कीमत भी उसी अनुरूप में बढ़ानी पड़ेगी तो क्या देश में महंगाई नहीं बढ़ जाएगी। बहरहाल इन सभी सवालों का जवाब भविष्य ही दे पाएगा। पर इतना अवश्य है कि किसी सरकार ने पहली बार किसानों, ग्रामीणों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर एक साथ इतना खर्च करने का साहस किया है। यही इस बजट की उपलब्धि है। ❑❑

# संतुलित विकास पर फोकस

बजट 2016–17 प्रस्तुत हो चुका है। जब पिछले साल वित्तमंत्री ने अपना बजट पेश किया था, तो भी देश की गुलाबी तस्वीर पेश की गई थी। बजट पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण में इस बार भी अर्थव्यवस्था की सुनहरी तस्वीर पेश की गई है। पिछले साल से बेहतर जीडीपी ग्रोथ (7.6 प्रतिशत), महंगाई पर नियंत्रण (5.6 उपभोक्ता महंगाई और शून्य से नीचे थोक महंगाई की दर), विदेशी भुगतान में घाटा भी पहले से कम और पहले से बेहतर औद्योगिक उत्पादन की दर, सभी अर्थव्यवस्था की बेहतर स्थिति की ओर इंगित कर रहे हैं।

ऐसी परिस्थितियों में अर्थव्यवस्था का हर वर्ग बजट से ज्यादा हिस्सा चाहता था। मध्यम वर्ग आयकर की स्लैब को बढ़ाने की अपेक्षा कर रहा था, तो उद्योग सोच रहा था कि 'मेक इन इंडिया' के लिए किस प्रकार की छूटें दी जाएंगी, गरीब की अपेक्षा थी कि सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर खर्च बढ़ाएगी। शेयर बाजार के लोग जो जबरदस्त घाटे से गुजर रहे थे, सोच रहे थे कि सरकार कुछ ऐसा करे ताकि शेयर बाजार दुबारा बढ़ जाए।

*मंदी का बहाना बनाकर बड़ी–बड़ी कंपनियां अपनी नकदी का उपयोग पूंजी निर्माण में नहीं कर रही हैं। इन हालातों में वित्तमंत्री ने कारपोरेट को दी जाने वाली कई छूटों को वापिस लिया है। कंपनियों को यह कहा गया है कि यदि वे घटी हुई दर पर टैक्स देना चाहती हैं तो घिसावट और निवेश भत्ते के रूप में जो छूटें लेती थी, वो बंद करें।*

**– डॉ. अश्वनी महाजन**

## कारपोरेट की छूट हुई कम

बजट आने के बाद मध्यम वर्ग कुछ निराश है, क्योंकि आयकर की स्लैब नहीं बढ़ी और 5 लाख तक आमदनी पाने वालों को मात्र 3000 रूपए की कर की छूट मिली। बड़े कारपोरेट भी खुश नहीं हैं, क्योंकि पिछले बजट की घोषणा के अनुरूप कारपोरेट टैक्स नहीं घटाया गया है और साथ ही कारपोरेट को दी जा रही रियायतों को भी घटा दिया गया है। यह सही है कि मध्यम वर्ग की आयकर स्लैब बढ़ाने की अपेक्षा इसलिए भी सही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने से पहले इस प्रकार का वायदा जनता से किया था। जहां तक कारपोरेट टैक्सों का सवाल है हम देखते हैं कि बड़े–बड़े कारपोरेट तरह–तरह की छूटें प्राप्त कर अपने लाभों को बढ़ा रहे थे और उनकी संपत्तियां बढ़ती जा रही थी। मंदी का बहाना बनाकर बड़ी–बड़ी कंपनियां अपनी नकदी का उपयोग पूंजी निर्माण में नहीं कर रही हैं। इन हालातों में वित्तमंत्री ने कारपोरेट को दी जाने वाली कई छूटों को वापिस लिया है। कंपनियों को यह कहा गया है कि यदि वे घटी हुई दर पर टैक्स देना चाहती हैं तो घिसावट और निवेश भत्ते के रूप में जो छूटें लेती थी, वो बंद करें। लेकिन 5 करोड़ से कम की टर्न–ओवर वाली कंपनियों पर कारपोरेट टैक्स 30 प्रतिशत से घटाकर 29 प्रतिशत कर दिया गया है।

## गांव हैं खुश

गांव में रहने वाले लोग खुश होंगे कि ग्रामीण सड़कों पर खर्च बढ़ाया गया है। गांव

पहले से ज्यादा शहरों से जुड़ेंगे। सिंचाई की सुविधाओं में विस्तार, अगले 1000 दिनों में सभी गांवों में पूर्ण विद्युतीकरण जैसी कुछ घोषणाएं हैं जो गांवों में जीवन बेहतर कर सकती है। कृषि के बजट को बढ़ाकर इस साल 35984 करोड़ रूपए किया गया है, जो पिछले साल से कहीं ज्यादा है। कृषि बीमा की योजना भी किसानों को राहत दे रही है और 2016–17 के लिए 9 लाख करोड़ रूपए का कृषि ऋण जिसपर सरकार ब्याज में भी छूट देगी और इसके लिए 15 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान, कुछ ऐसे उपाय हैं जो कृषि को बेहतर बनाने की ओर काम कर सकते हैं। पंचायती राज और डिजीटल इंडिया कार्यक्रम के तहत भूमि संबंधी रिकार्डों का आधुनिकीकरण आदि के भी दूरगामी परिणाम हो सकते हैं।

### गरीबों के लिए भी हैं प्रावधान

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले डेढ़ करोड़ लोगों के लिए एलपीजी कनेक्शन हेतु 2000 करोड़ रूपए का प्रावधान, गरीबों के लिए एक लाख रूपए की राशि और वरिष्ट नागरिकों के लिए 130000 रूपए की राशि तक स्वास्थ्य सुरक्षा स्कीम, आम जन के लिए 3000 जन औषधी केन्द्र खोलने की योजना, 4950 डायलसिस केन्द्रों की स्थापना, अनुसूचित जाति–जनजाति के उद्यमियों के लिए विशेष योजना आदि कुछ अच्छी योजनाएं रखी गई हैं।

### इन्फ्रास्ट्रक्चर की ओर भी है ध्यान

वित्तमंत्री ने बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर पर विशेष जोर दिया है। न केवल पिछली लंबित परियोजनाएं पूरी हुई हैं, बल्कि राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजमार्गों समेत सभी सड़कों पर 55 हजार करोड़ रूपए के प्रावधान, रेलवे पर 1.21 लाख करोड़ रूपए समेत कुल इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 2.21 लाख करोड़ रूपए का कुल खर्च अभी तक का रिकार्ड माना जा सकता है। जलपोतों और हवाई अड्डो का आधुनिकीकरण, राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास आदि इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के कुछ सराहनीय कदम माने जा सकते हैं। यात्री परिवहन के क्षेत्र में परमिट राज की समाप्ति की ओर भी यह बजट कदम बढ़ा रहा है, जिससे सड़क यातायात में विकास संभव है।

### और भी बढ़ सकते थे संसाधन

हालांकि पिछले साल के 17.77 लाख करोड़ रूपए के बजट की तुलना में इस साल 19.78 लाख करोड़ रूपए के खर्च वाला बजट सरकार के खर्च को 11 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ा रहा है, लेकिन

**जलपोतों और हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण, राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास आदि इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के कुछ सराहनीय कदम माने जा सकते हैं। यात्री परिवहन के क्षेत्र में परमिट राज की समाप्ति की ओर भी यह बजट कदम बढ़ा रहा है।**

वित्तमंत्री इस वृद्धि को और ज्यादा कर सकते थे। गौरतलब है कि पिछले साल के बजट में वित्तमंत्री ने राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3.9 प्रतिशत तक सीमित रखने और वर्ष 2016–17 के लिए इस घाटे को और घटाकर जीडीपी के 3.5 प्रतिशत तक लाने की बात कही थी। हालांकि इस विषय में सभी अर्थशास्त्रियों की राय एक जैसी नहीं थी और देश में डिफ्लेशन यानि मंदी जैसे हालातों के कारण यह माना जा रहा था कि इस बार राजकोषीय घाटे को बढ़ाकर अतिरिक्त संसाधन जुटाए जा सकते थे। लेकिन वित्तमंत्री ने पिछले बजट में दिए गए वचन पर टिके रहने की बात की। लगभग यही बात नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगरिया ने भी एक टीवी शो के दौरान कही। गौरतलब है कि यदि राजकोषीय घाटे को 4 प्रतिशत तक रखा जाता तो सरकार को बजट के लिए 60 हजार करोड़ रूपए अतिरिक्त मिल सकते थे।

### खाद्य उत्पादों की मार्केटिंग में विवादास्पद एफडीआई नीति

देश गवाह है कि पिछली यूपीए सरकार जब खुदरा क्षेत्र में एफडीआई की नीति को अनुमति का बिल लेकर आई तो उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी समेत कई राजनीतिक दलों ने किया। हालांकि राजनीतिक बहुमत उस बिल के साथ नहीं था, उस समय राजनीतिक दलों ने अपने स्वार्थों के कारण उस बिल से अनुपस्थित रहकर या अपने विचारों के विरूद्ध भी समर्थन देकर जब पारित करवाया जो उस समय भारतीय जनता पार्टी ने उसका पुरजोर विरोध किया था। 2014 के आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा–पत्र में जीतने पर इस नीति को बदलने की बात कही थी। चुनाव जीतने के बाद हालांकि सरकार ने नीति नहीं बदली, लेकिन संबंधित मंत्रियों ने यह बारंबार कहा कि खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश को अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन इस बजट में अचानक भारत में उत्पादित खाद्य पदार्थों की मार्केटिंग के लिए 100 प्रतिशत एफडीआई की घोषणा ने देश को स्तब्ध कर दिया है। घोषित नीति के अनुसार अब विदेशी खाद्य पदार्थों की बिक्री कर सकेंगी यानि सीधेतौर पर यह खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश को अनुमति देने वाली नीति है। इस नीति के कारण देश में करोड़ों छोटे दुकानदारों के रोजगार पर तो प्रभाव पड़ेंगा ही साथ ही किसान भी विदेशी कंपनियों के रहमो–करम पर आ जाएंगे। सरकार की इस नीति को किसी भी हालत औचित्यपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता। ❑❑

## बजट 2016

# जरूरी है किसानों की आय बढ़ाना

**भारत** के 17 राज्यों में खेती से एक किसान की औसत आय 20 हजार रुपये सालाना है। इसमें उत्पादन का वह अंश भी शामिल है जिसे वह पारिवारिक उपभोग के लिए रखता है। दूसरे शब्दों में, इन राज्यों में किसान की औसत मासिक आय महज 1,666 रुपये है। जी हां, आपने सही पढ़ा, महज 1,666 रुपये।

इस तस्वीर में आप खुद को रख कर देखें कि अगर आप किसान होते और आप पूरे महीने में सिर्फ 1,666 रुपये कमा पाते, तो आप क्या करना पसंद करते? आप पांच साल और इंतजार करते? उम्मीद पर जीते रहते, और सोचते रहते, वो सुबह कभी तो आयेगी!

जब बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने संसद में यह कहा कि 'हमें 'खाद्य सुरक्षा' से परे सोचना होगा और किसानों में 'आय सुरक्षा' का भरोसा देना होगा', मैं सांस थामे इंतजार कर रहा था। लेकिन जब उन्होंने 2022 तक किसानों की आय दुगुना करने का वादा किया, तो मेरी सारी उम्मीदें टूट गयी। वित्तमंत्री की इच्छा है कि किसान पांच सालों तक इंतजार करें। पांच साल के बाद अगर यह वादा पूरा भी हो जाता है तो इन 17 राज्यों में किसानों की मासिक आय 3,332 रुपये हो जायेगी।

मैं कल्पना कर सकता हूं कि 2022 में पेश होने वाली आर्थिक समीक्षा में गर्व से घोषणा की जायेगी कि लगातार प्रयासों से सरकार किसानों की आय दुगुनी करने में सफल रही है। अर्थशास्त्री निश्चित तौर पर इसे बड़ी उपलब्धि के रूप में चिन्हित करेंगे। अगर मुद्रास्फीति के हिसाब को जोड़ कर देखें, तो तब भी 3,332 रुपये की आय 1,666 रुपये के बराबर होगी जो आमदनी किसान की आज है। इस लिहाज से एक अर्थ में सरकार ने 'आय सुरक्षा' का वादा किया है।

ऐसे समय में जब कृषि क्षेत्र गंभीर संकट से जूझ रहा है और पिछले कई सालों से जारी संकट का उल्लेख 2016 की आर्थिक समीक्षा में भी विस्तार से किया गया है, मुझे आशा थी कि

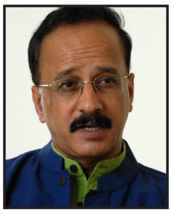

*2022 में पेश होने वाली आर्थिक समीक्षा में गर्व से घोषणा की जायेगी कि लगातार प्रयासों से सरकार किसानों की आय दुगुनी करने में सफल रही है। अर्थशास्त्री निश्चित तौर पर इसे बड़ी उपलब्धि के रूप में चिन्हित करेंगे।*

**– देविंदर शर्मा**

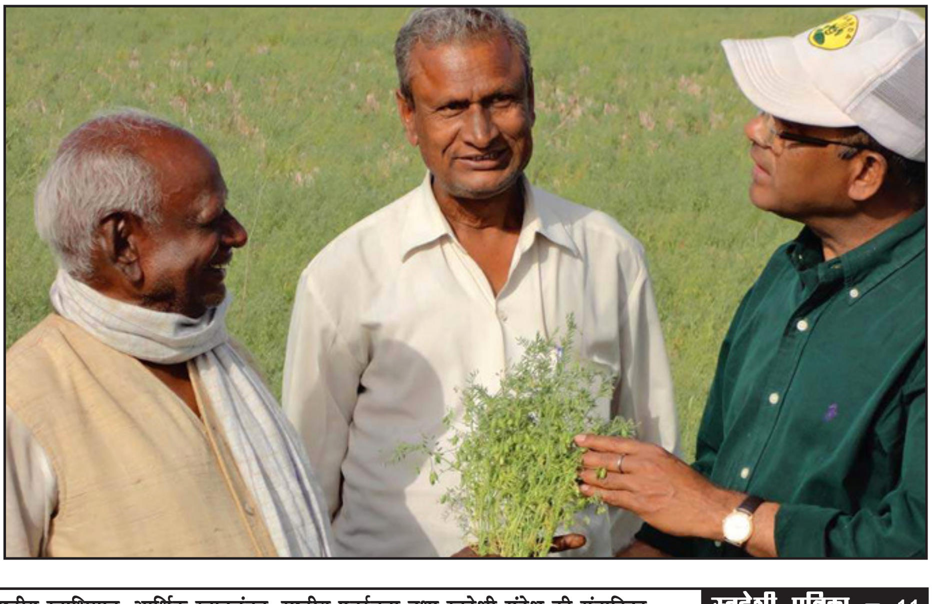

सरकार इस दिशा में कोई त्वरित कदम उठायेगी। देश में किसानों की आत्महत्या का प्रति दिन औसत 42 से बढ़कर 2015 में 52 हो गया है। ऐसी स्थिति में कृषि पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है।

बजट भाषण में करीब 50 बार कृषि का उल्लेख कर देने भर से लापरवाही और उदासीनता झेल रहे इस क्षेत्र को राहत नहीं मिल सकती है।

खेती का मौजूदा संकट कम कृषि उत्पादन का परिणाम नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसान ऊपज बढ़ाना नहीं जानते और इसी कारण उनकी आमदनी नहीं बढ़ रही है। उत्पादकता महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके लाभकारी मूल्य नहीं मिलने के कारण किसान परेशान है। उदाहरण के लिए भारत के प्रमुख खेतिहर राज्य पंजाब को देखें, पंजाब के किसान 99 फीसदी निश्चित सिंचित क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर 4,500 किलोग्राम गेहूं और 6,000 किलोग्राम धान उपजाते हैं।

यह निश्चित रूप से फसल उत्पादकता का बहुत उच्च स्तर है। बजट में सरकार द्वारा घोषित सिंचाई सुविधा के विस्तार समेत सभी विकास सूचियां पंजाब में पहले से ही उपलब्ध हैं। इसके बावजूद, जैसा कि कृषि व्यय एवं मूल्य आयोग के आंकड़ों में बताया गया है, राज्य में एक हेक्टेयर जमीन में धान और गेहूं की पैदावार से सालाना 36 हजार रुपये की कुल आमदनी होती है यानि हर महीने मात्र तीन हजार रुपये।

इस राशि की तुलना सातवें वेतन आयोग के बाद मिलने वाले एक चपरासी के 18 हजार रुपये के मूल मासिक वेतन से करें, मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर नया भर्ती हुआ चपरासी भी आय करदाताओं की श्रेणी में आ जाये।

इसलिए इस वर्ष की आर्थिक समीक्षा की यह बात सही नहीं है कि भारतीय कृषि की मुख्य चुनौती निम्न उत्पादकता है। यह स्पष्ट करना होगा कि असली चुनौती वह है, जिसे वित्तमंत्री ने चिन्हित किया है– 'आय सुरक्षा'।

किसानों की बात करने पर मुख्यधारा के अर्थशास्त्री और मीडिया तुरंत ही आपको वामपंथी करार दे देते हैं। कई टेलीविजन चौनलों पर यह देख कर मुझे बहुत धक्का लगा कि पैनल में बैठे लोग बजट में 'कृषि' शब्द पर जोर देने से स्पष्ट रूप से निराश थे। जो बात नहीं समझी जा रही है, वह यह है कि कृषि अनुत्पादकता या कम कमाई के कारण दुसाध्य नहीं हुई है, बल्कि इसे जान–बूझकर वर्षों से कुपोषित रखा गया है। वर्ष 1970 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 76 रुपये प्रति कुंतल था। वर्ष 2015 में, 45 सालों के बाद, इसमें 19 गुणा वद्धि हुई और इसकी दर 1,450 रुपये प्रति कुंतल हो गयी। इसी अवधि में सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन (महंगाई भत्ते के साथ) में 120 से 150 गुणा बढ़ोतरी हुई, कॉलेज शिक्षकों और विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों के वेतन 150 से 170 गुणा, स्कूली शिक्षकों के वेतन 280 से 320 गुणा, और उद्योग जगत के शीर्ष अधिकारियों के वेतन 1,000 गुणा तक बढ़े।

**न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिहाज से देखें, तो किसानों की आय में सिर्फ 3.2 से 3.6 फीसदी की मामूली वार्षिक वृद्धि हुई है।**

विगत 45 वर्षों में कर्मचारियों के वेतन में भारी वृद्धि होती रही, किसान अपने उचित बकाये के लिए तरसते रहे। अगर गेहूं की कीमतें कम–से–कम 100 गुणा भी बढ़ायी जाती, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य कम–से–कम 7,600 रुपये प्रति कुंतल होता। इस पर तर्क यह दिया जाता है कि अगर गेहूं की कीमतें बढ़ीं, तो खाद्य मुद्रास्फीति बहुत अधिक बढ़ जायेगी. इससे स्पष्ट है कि सिर्फ खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने के लिए सालों से किसानों को दंडित किया जाता रहा है।

यही कारण है कि एनडीए सरकार कृषि लागत के ऊपर 50 फीसदी लाभ देने के अपने वादे से पीछे हट गयी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिहाज से देखें, तो किसानों की आय में सिर्फ 3.2 से 3.6 फीसदी की मामूली वार्षिक वृद्धि हुई है। साफ है कि संगठित क्षेत्र में हर व्यक्ति के वेतन में भारी वृद्धि होती रही, और जान–बूझकर किसानों की अवहेलना की जाती रही।

मेरी राय में सरकार को अपनी 'किसान–विरोधी' छवि में सुधार के लिए यह उचित समय था। कृषि में सार्वजनिक निवेश में बढ़ोतरी के साथ आय बढ़ाने के उपाय भी लाये जाने चाहिए थे। यदि सरकार किसानों की मदद के लिए तीन लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज दे देती और किसानों की आय सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित कर देती, तो समूची अर्थव्यवस्था का कायाकल्प हो सकता था।

देश के 60 करोड़ किसानों के हाथ में अधिक आय न सिर्फ उन्हें 'आय सुरक्षा' प्रदान करती, बल्कि इससे घरेलू मांग में भारी वृद्धि होती जिससे औद्योगिक वृद्धि को तेज गति मिलती। वास्तव में, 'सबका साथ–सबका विकास' का यही एकमात्र तरीका है। ❑❑

# बचत को प्रोत्साहित करने की दरकार

**भारतीय अर्थव्यवस्था** एक अजीब संकट के दौर से गुजर रही है। स्टॉक मार्किट गिर रही है, रूपया ऐतिहासिक गति से नीचे जा रहा है, आधारभूत तथा भूमि भवन उद्योग बैंकों को लूट रहा है, बैंक इनके हजारों करो के ऋण खाते से हटा रहे है–माफ कर रहे है। बैंक इससे आगे भी जा रहे है। गरीबों की जमाराशि से चलने वाले बैंक सौगात में बड़ी कंपनियों के लिए ब्याज दर कम कर रहे है। आम आदमी हर तरह से लूट रहा है। उसके धन की खुलेआम लूट हो रही है और यह कहते हुए कि बैंक को घाटा हो रहा है, बैंक हर तरह के चार्ज बढ़ा रहे है। गरीब जनता तो लूटने के लिए ही पैदा हुई है। उसकी पूँजी से बड़े उद्योगपति फल–फूल रहे है। गरीब जनता ही नहीं सरकार को भी घाटे की भरपाई को पूरा करने को मजबूर किया जा रहा है। यानि जनता द्वारा दिए गए कर पर भी डाका डाला जा रहा है। सरकार ने 2014–15 के बजट में इस घाटे को सामाजिक क्षेत्र–शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में कम निवेश कर इस घाटे को पूरा करने की कोशिश की।

स्टॉक मार्किट फरवरी 11 को एक ही दिन में 807 अंक नीचे गिरकर 22951 के सेंसेक्स पर आ गया। इसका प्रमुख कारण था–स्टेट बैंक के मुनाफे में 62 प्रतिशत की कमी होना। स्टेट बैंक का मुनाफा रूपया 2910 करोड़ से रूपया 1200 करोड़ पर आ गया। इस पर भी लोग प्रश्नचिन्ह लगा रहे है। इसकी दूसरी वजह अमरीकी अर्थव्यवस्था में आने वाला सुधार भी है। वहां ब्याज दर बढ़ने से विदेशी संस्थागत निवेशक जनवरी से रुपया 14,000 करोड़ के शेयर बेचकर लगभग 2 बिलियन ले गया। इससे म्यूच्यूअल फंड, जिसमें आम आदमी का पैसा यह कह कर लगाया जाता है कि इससे उसे लाभ मिलेगा, घाटे में जाने लगा है।

सिर्फ निवेशक ही नहीं, राष्ट्रीय पेंशन योजना में निवेश करने वाले करोड़ों सरकारी कर्मचारियों को इससे बहुत घाटा हो रहा है। इससे सिर्फ कर्मचारियों को ही घाटा नहीं हो रहा है, सरकार इस धन का गारंटर है, उसे भी इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। यानि कि अर्थव्यवस्था

*सिर्फ निवेशक ही नहीं, राष्ट्रीय पेंशन योजना में निवेश करने वाले करोड़ों सरकारी कर्मचारियों को बहुत घाटा हो रहा है। सिर्फ कर्मचारियों को ही घाटा नहीं हो रहा है, सरकार इस धन का गारंटर है, उसे भी इसकी भरपाई करनी पड़ेगी।*

**– शिवाजी सरकार**

पर चौतरफा चोट पहुंच रही है।

रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने अंततः एक सही आवाज उठाई है। उन्होंने कहा है कि बैंकों की सर्जरी होनी चाहिए जिससे बुरे कर्ज के बोझ से वे मुक्त हो सके। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने आधारभूत निवेशों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। अगर वे यह न करते तो अर्थव्यवस्था में गति नही आती। एस.बी.आई., बैंक ऑफ बरोदा और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) को इनमें सबसे ज्यादा घाटा हुआ और सिंडिकेट तथा HDFC को सबसे कम। सारे बैंकों का मिलाकर लगभग रूपया 4.04 करोड़ के घाटे की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि वस्तुतः घाटा इससे कहीं ज्यादा है।

राष्ट्रीयकरण से पूर्व इन बैंकों के मालिक थे और तब भी जनता के पैसे का दोहन करते थे। राष्ट्रीयकरण के बाद भी वहीं इनका दोहन कर रहे है। जनता तो हर हाल में उनका शिकार ही बनती है।

सुप्रीम कोर्ट ने आखिर इसका संज्ञान लेते हुए रिजर्व बैंक से कहा कि 500 करोड़ रुपये से ज्यादा ऋण लेने वाली कंपनियों का नाम उन्हें बताया जाए। अगर ऋण लेने वाले किसान होते तो बैंक उनका नाम पंचायत में चस्पाकर उनको शर्मिंदा करते और उन्हें आत्महत्या करने को मजबूर करते। परंतु बड़े अपराधियों को शर्मिंदा वे नहीं करते हैं क्योंकि कई बैंक बोर्ड में वे स्वयं या उनके नुमायांदे मौजूद होते है। यहां एक बात समझने की है कि बैंकों का

**अगर ऋण लेने वाले किसान होते तो बैंक उनका नाम पंचायत में चस्पाकर उनको शर्मिंदा करते और उन्हें आत्महत्या करने को मजबूर करते।**

खस्ताहाल आर्थिक गति के धीमी होने से नहीं है, बल्कि इसका उल्टा ही है। इनकी वजह से गति धीमी हो रही है।

बैंकों का कहना है कि बड़े ऋण लेने वालों ने अपनी मांग को बढ़ाकर प्रस्तुत किया। पिछले दस वर्षों में इसका फायदा लेकर वे ऋण को जिस काम के लिया लिया था उस पैसे को अन्य क्षेत्रों में लगा दिया। रियल एस्टेट ने तो यह काम सबसे ज्यादा किया। इसका नतीजा हमें दिल्ली–नॉएडा–गाजियाबाद–गुडगाँव–फरीदाबाद क्षेत्र में 2 लाख से अधिक फ्लैट के न बिकने में दिखता है। कई अन्य बड़े शहरों में भी ऐसा ही हो रहा है।

ग्रेटर नॉएडा को आज विश्व का सबसे बड़ा निर्जन–जहाँ कोई नहीं रहता है, शहर माना गया है। यहाँ के जयप्रकाश समूह ने 2008 से बैंकों के लगभग 95,000 करोड़ रुपये नहीं चुकाये है, विजय माल्या की कंपनियों ने 700 करोड़ रुपए नहीं चुकाए है। फेहरिश्त बहुत लम्बी है।

CRISIL के अध्ययन में बताया गया है भारत को 6 लाख करोड़ का निवेश प्रतिवर्ष मार्च 2020 तक करना है, यानि की 30 लाख करोड़ रूपए की आवश्यकता है – बिजली क्षेत्र, सड़क, टेलिकॉम, ट्रांसपोर्ट और शहरी क्षेत्र के विकास में लगाने की।

क्या हम एक असंभव काम कर रहे है? शायद नहीं। अगर विकास की गति और दिशा सही रहे और विकास 5 प्रतिशत की दर से भी होता रहे तो यह कोई बड़ी रकम नहीं है। परंतु यह हो नहीं रहा है। बाजार में मांग नहीं है। महंगाई की ऊँची दर से लोग परेशान है। उनके पास खरीदारी के लिए पैसे नहीं है। लगभग 70 प्रतिशत परिवारों की आमदनी रुपये 4000 से 7000 प्रतिमास है। उनकी कम क्रयशक्ति को देखते हुए यह पूँजी बहुत ज्यादा लगती है। इसके लिए उचित योजना बनाने की आवश्यकता है। नीति आयोग को यह शोध करना चाहिए।

रिजर्व बैंक का कहना है कि आधारभूत क्षेत्र का यह ऋण जून 2014 में 22.9 प्रतिशत था। जून 2015 तक यह 24 प्रतिशत हो गया। पिछले दस सालों में इस क्षेत्र का ऋण कुल बैंक पूँजी का 28 प्रतिशत हो गया है। यह अन्य क्षेत्र से कई गुना ज्यादा है। इस क्षेत्र में 2005 में बैंक ऋण का हिस्सा 5 प्रतिशत था, 2015 में यह 15 प्रतिशत हो गया है। इसका तात्पर्य है कि कुल 8.5 लाख करोड़ रुपये आधारभूत ऋण में दिये गए, आज लगभग 2 लाख करोड़ रुपये बत्तेखाते में दिख रहा है, यह रिजर्व बैंक कहता है। रघुराम राजन कहते है कि बड़ी कंपनियों ने बहुत अधिक उधार लिया है। ये वहीं कंपनियां हैं जो

वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां भी अनुकूल नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष (IMF) ने विश्व में समस्या का उल्लेख करते हुए कहा है कि भारत एक उज्जवल क्षेत्र है। पर वैश्विक बाजार में मंदी से भारत का निर्यात घट रहा है और देश में मांग कम होने से उत्पादन कम हो रहा है। समस्या पूरे यूरोप और एशिया में है। भारत से पूँजी लगातार हट रही और अब अगर भारत ने ऋण दर नहीं बढ़ाये तो पूँजी का पलायन अमरीका को होना स्वाभाविक है।

पेट्रोल के दाम में जो कमी आई है उसका लाभ भी देश की जनता या

अर्थव्यवस्था को नहीं मिला।

आर्थिक संकट बैंकों के कुप्रबंधन से गहरा रहा है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 1997–98 की दक्षिण–पूर्व एशिया का संकट भी बैंकों में आधारभूत क्षेत्र में होने वाले तीव्र घाटे से ही हुआ था। विश्व बैंक ने उस समय भी चेतावनी दी थी। बैंकों ने चेतावनी तो नहीं सुनी। पर बड़ी कंपनियों को एक और सूत्र जनता के धन पर डाके का जरूर मिल गया। आज अगर बड़ी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई और उनसे जनता के धन के वसूली नहीं होती है तो यह संपूर्ण देश के अर्थवयवस्था के लिए विकट संकट के रूप में दिखेगी।

इस समस्या का सबसे बड़ा कारण ब्याज दरों का कम होना है। इससे पूँजी के लूटेरों को बड़ी सहूलियत हो जाती है।

आम लोगों को इससे लगातार घाटा होता है। आम जमाकर्ता हर हाल में नुक्सान उठाता है। बैंक में पैसा जमा करने से उसके धन का वास्तविक वास्तविक मूल्य, कम ब्याज दर से ऊँची महंगाई से, कम होता जाता है। वृद्ध, गृहणी, जन–धन योजना में जमा करने वालों की पूँजी कम होती जाती है।

सस्ती ब्याज दर बड़े लूटेरों को राहत देती है। इसलिए जो लोग ब्याज दर कम करने की बात करते है वे देश के लोगों के साथ गद्दारी कर रहे है चाहे वे उद्योगपति हो या नौकरशाह।

जनता के धन की सुरक्षा के लिए जमाराशि पर न्यूनतम ब्याज दर 9 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। ऋण पर दर इससे अधिक ही होनी चाहिए। ब्याज दर अगर ऊँची होगी तो कोई भी बड़ा समूह अपनी जरूरत को बढ़ाकर पेश नहीं करेगा, न ही एक काम के लिए लिया गया पैसा दूसरे काम में लगायेगा।

यह कहना भी सही नहीं है कि सिर्फ बड़े घराने ही इस परिस्थिति के लिए जिम्मेदार है। बैंक और अफसरशाही भी इस खेल में शामिल है। वे दक्षिण–पूर्व एशिया के संकट के लिए भी जिम्मेदार थे। भारत के बैंक अफसर इससे अछूते नहीं हैं। बैंकों ने ऋण का कैसे उपयोग हुआ इस पर कोई नजर नहीं रखी। बैंक जनता के पूँजी के संरक्षक है। उनकी अपनी कोई पूँजी नहीं है। अगर बैंकों को घाटा हो रहा है तो अफसरों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इस पर सभी चुप्पी साधे है। इसमें कुछ राजनीतिक दल जो 2004 से 2014 तक सत्ता में थे उनके कुछ नेता भी शामिल है। सरकार बदल गई है अब तो कार्रवाई होनी चाहिए।

संकट गंभीर है। इससे निबटने के लिए सबसे पहले ब्याज दर जमाराशि पर बढ़ाने की आवश्यकता है। ऋण समुचित दर पर मिलेगा तो जनता का धन सुरक्षित भी रहेगा और उसकी धन वापसी भी सुरक्षित रहेगी।

पुरानी कहावत–'सस्ता रोये बारबार, महंगा रोये एकबार', यहां भी लागू होती है। बैंकों और जनता की पूँजी की सुरक्षा की शुरुआत ब्याज दर को वास्तविक महंगाई दर पर लाने से ही होगी। देश के उद्योगों की रक्षा तभी होगी जब जनता का धन सुरक्षित रहेगा। हर पूँजी सार्वजनिक है। इस देश में कोई व्यवसाय निजी नहीं है। बड़े पूंजीपति का अर्थ है कि उसने जनता के ज्यादा धन पर कब्जा कर रखा है।

हमें जनता के और बैंक धन के सुरक्षा के कदम अगर आज किसी दबाव में नहीं उठाए तो 1997–98 की दक्षिण–पूर्व एशिया जैसा तीव्र संकट के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, इसलिए समय रहते हम सही कदम उठाएं। ❑❑

# अर्थव्यवस्था को गति देने के उपाय

*वित्तमंत्री ने कहा है कि बजट के प्रावधानों के कारण इनकम टैक्स में कटौती तथा एक्साइज ड्यूटी में वद्धि होगी। दोनों बदलाव का सम्मिलित प्रभाव 19,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होगा। लेकिन यह छोटी सी रकम भी निवेश के लिये उपलब्ध नहीं होगी चूंकि सातवें वेतन आयोग तथा राज्यों तथा पंचायतों को बढ़े हुये अनुदान में दो लाख करोड़ का अतिरिक्त खर्च होने का अनुमान है।* – **डॉ. भरत झुनझुनवाला**

**बजट भाषण** में वित्तमंत्री ने स्वीकार किया है कि वित्तीय घाटे के संबंध में उन्हें दो परस्पर विरोधी सलाह मिली है। एक सलाह है कि वित्तीय घाटे पर सख्ती से नियंत्रण किया जाये। दूसरी सलाह है कि इसमें छूट दी जाये। सरकार की आय की तुलना में खर्चों की अधिकता को वित्तीय घाटा कहा जाता है। सरकार को टैक्स 100 रुपए मिले तथा खर्च 110 रुपए हो तो वित्तीय घाटा 10 रुपए हुआ। घाटे की इस रकम को सरकार ऋण लेकर पूरा करती है। जैसे परिवार की आय 10,000 रुपए हो और मालिक से 2,000 रुपए का लोन लेकर मासिक खर्च 12,000 रुपए का किया जाए तो वित्तीय घाटा 2,000 रुपए हुआ। लोन लेकर बच्चे की पढ़ाई की फीस दी जाए तो लोन लेना सार्थक हुआ। वहीं लोन लेकर परिवार का मुखिया शराब पिये तो लोन लेना घातक हो जाता है। इसी प्रकार लोन लेकर सरकार निवेश करे तो वित्तीय घाटा सार्थक होता है जबकि लोन लेकर सरकार खपत करे तो वहीं वित्तीय घाटा हानिप्रद हो जाता है।

वर्तमान समय मे वित्तमंत्री के हाथ बंधे हुए है। सातवें वेतन आयोग के कारण सरकारी खपत में एक लाख करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की विशाल बढ़त होने को है। ऐसे में वित्तीय घाटे पर नियंत्रण करने का अर्थ होगा कि जो थोड़ा सरकारी निवेश हो रहा है उसमें भी कटौती कर दी जाए। जैसे परिवार का मुखिया उधार लेकर शराब पीता है। ऐसे में उधार लेना बंद कर दिया जाए और शराब पीना जारी रखा जाए तो गृहणी के लिए एक मात्र उपाय होता है कि बच्चे की स्कूल की फीस तथा गर्भवती बहू के दूध में कटौती करे। ऐसे में लोन लेते रहना ही उचित होता है।

वित्तीय घाटे पर नियंत्रण करने का दूसरा कारण निवेश को आकर्षित करने का बताया जाता है। मान्यता है कि वित्तीय घाटे पर नियंत्रण करने को सरकारे अपने खर्च घटायगी। सरकार को टैक्स कम वसूल करने होंगे। सरकार को लोन भी कम लेने होंगे। सरकार को

लोन देने के लिए रिजर्व बैंक को नोट भी कम छापने होंगे। इससे महंगाई पर नियंत्रण होगा। घरेलू एवं विदेशी निवेशकों को देश की अर्थव्यवस्था पर भरोसा बनेगा। वे भारत में निवेश करने को तत्पर होंगे। वित्तीय घाटे पर नियंत्रण करने के लिए सरकार द्वारा निवेश में जो कटौती की जायेगी उससे ज्यादा निवेश निजी स्त्रोतों से आयेगा और अर्थव्यवस्था चल निकलेगी।

यह फार्मूला संभवतः उस समय सफल हो सकता था जब विश्व अर्थव्यवस्था में तेजी थी जैसे नब्बे के दशक में। तब भारत में वित्तीय स्थिरता को देखकर बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहां आकर उत्पादन करती चूंकि उन्हें अपने घरेलू बाजार में सप्लाई करने के लिए माल का बढ़कर उत्पादन करना था। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिरता को देखते हुए जनरल मोर्टर्स ने चेनै में कार उत्पादन का कारखाना लगाया और कार का उत्पादन करके अमरीका को निर्यात किया। वर्तमान में ऐसा निवेश नहीं आयेगा चूंकि विश्व अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में है। ऐसे में वित्तीय घाटे पर नियंत्रण करना डबल घातक हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा खर्च में कटौती करने से घरेलू मांग में गिरावट आएगी। साथ में विदेशी मांग पहले ही पस्त है।

वित्तमंत्री के हाथ बंधे हुए है। सरकारी खर्च पर लगाम लगाना संभव नहीं है। सरकारी निवेश में वृद्धि करना भी संभव नहीं है। इस दुरूह परिस्थिति में वित्तमंत्री को रास्ता निकालना था। उपाय था कि तमाम कल्याणकारी योजनाओं को समाप्त करके रकम को परिवारों के बैंक खातों में सीधे डाल दिया जाता। वर्तमान में सरकार द्वारा लगभग 6 लाख करोड़ रुपए प्रतिवर्ष खाद्य सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी, केरोसीन एवं एलपीजी सब्सिडी, मनेरगा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा में किया जाता है। यह रकम मुख्य रूप से सरकारी कर्मियों के वेतन तथा भ्रष्टाचार में खप जाती है जैसे खाद्य सब्सिडी फूड कार्पोरेशन की नौकरशाही में खप जाती है। इन तमाम कल्याणकारी कार्यक्रमों को एक झटके में समाप्त करके इस विशाल रकम को देश के 25 करोड़ परिवारों के खातो में सीधे डाला जा सकता है। वर्तमान में ही खर्च की जा रही रकम से हर परिवार को हर माह 2,000 रुपए दिये जा सकते है। पूरे देश के अच्छे दिन तत्काल आ जायेंगे। लोगों द्वारा बाजार से साइकिल तथा कपड़े खरीदे जायेंगे और अर्थव्यवस्था चल निकलेगी।

**सरकार द्वारा लगभग 6 लाख करोड़ रुपए प्रतिवर्ष खाद्य सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी, केरोसीन एवं एलपीजी सब्सिडी, मनेरगा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा में किया जाता है।**

दूसरा उपाय है कि सभी सरकारी योजनाओं के अंतिम प्रभाव का आकलन कराया जाए। इन्हे रैंक करके नीचे की दस प्रतिशत योजनाओं को हर वर्ष समाप्त करके ऊपर की दस प्रतिशत योजनाओं के अनुदान को डबल कर दिया जाए। इससे सरकार के वर्तमान खर्चों की गुणवत्ता में सुधार आएगा। वर्तमान में व्यर्थ हो रही रकम प्रभावी हो जाएगी और अर्थव्यवस्था चल निकलेगी।

तीसरा उपाय है कि सातवें वेतन आयोग के कारण सरकारी कर्मियों के वेतन में जो वृद्धि होगी उसे नगद के स्थान पर इन्फ्रास्ट्रक्चर बांड के रुप में दिया जाए। ऐसा करने से एक तीर से दो लक्ष्य हासिल होंगे। सरकारी कर्मियों को वेतन वृद्धि हासिल होगी और देश को इन्फ्रास्ट्रकचर मिलेगा।

वर्तमान सरकार का तिहाई कार्यकाल बीत चुका है। बातें बहुत हैं परंतु अच्छे दिनों का इंतजार है। तत्काल सही दिशा में कठोर कदम उठाने की जरूरत थी।

वित्तमंत्री के सामने एकमात्र उपाय था कि वित्तीय घाटे में ढील देते। ऋण लेकर सड़क आदि में निवेश बढ़ाते। साथ–साथ सरकारी खर्चों की गुणवत्ता पर सुधार में ध्यान देते। ऐसा करते तो वास्तव में सरकारी निवेश बढ़ता। वित्तमंत्री ने फिर भी निवेश बढ़ाने की तमाम घोषणायें की हैं। लेकिन इनके लिये धन कहां से आयेगा इसका समुचित उत्तर उपलब्ध नहीं है।

वित्तमंत्री ने कहा है कि बजट के प्रावधानों के कारण इनकम टैक्स में कटौती तथा एक्साइज ड्यूटी में वृद्धि होगी। दोनों बदलाव का सम्मिलित प्रभाव 19,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होगा। लेकिन यह छोटी सी रकम भी निवेश के लिये उपलब्ध नहीं होगी चूंकि सातवें वेतन आयोग तथा राज्यों तथा पंचायतों को बढ़े हुये अनुदान में दो लाख करोड़ का अतिरिक्त खर्च होने का अनुमान है। इसलिये पूर्व के निवेश को बचा पाना ही कठिन है। वित्तमंत्री ने निवेश की जो घोषणायें की हैं उनपर भरोसा नहीं बनता। वित्तमंत्री को ऊपर बताये कठोर कदम उठाने थे जिनसे वे पीछे हट गये। ❑❑

# युवा सपनों का बजट

**वित्तमंत्री अरुण जेटली** का बजट पर भाषण अभी चल ही रहा था कि सोशल मीडिया पर युवाओं की सकारात्मक प्रतिक्रियायें आनी शुरु हो गयी जो यह दर्शा रही थी कि ये युवाओं के सपनों का बजट है। मेरे एक पूर्व छात्र, जो एमबीए करने के बाद अपनी नई कंपनी शुरु करने जा रहा है, ने अपने फेसबुक वाल पर लिखा कि मोदी जी को वोट सार्थक हुआ। यह टिप्पणी उन करोड़ों युवाओं की मनस्थिति को दर्शाने वाला है, जिन्होंने उच्च गुणवत्ता की शिक्षा और रोजगार की बेहतर संभावनाओं के सपनों को संजोकर भाजपा को लोकसभा चुनावों में वोट दिया था। 2016 के बजट में जेटली ने इनकी उम्मीदों को हकीकत में उतारने के लिए एक लम्बी छलांग लगाई है।

देश की जनता को शिक्षा सहज ही सुलभ हो इसके लिए इस बार के बजट में विशेष प्रावधान किये गये हैं। शिक्षा को समर्पित मानव संसाधन विकास मंत्रालय को 72394 करोड़ रुपये बजट में आवंटित किये गये हैं जो अब तक का सर्वाधिक है। इसी क्रम में वित्तमंत्री ने इस बजट में राष्ट्रीय शिक्षा मिशन को 28010 करोड़ रुपये दिये। साथ ही जिन जिलों में अभी तक नवोदय विद्यालय नहीं खोले गये है, ऐसे सभी 62 जिलों में नवोदय विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है। 'पढ़ेगा इण्डिया, तभी बढ़ेगा इण्डिया' के नारे को वास्तविक रुप प्रदान करने के लिए दस सरकारी और दस निजी संस्थाओं को विश्व स्तरीय अनुसंधान केन्द्र युक्त शिक्षण संस्थान बनाने का प्रस्ताव भी इस बजट में किया गया। जेटली के इन प्रयासों से भारतीय शिक्षा की तस्वीर निश्चित सुधरेगी।

*'पढ़ेगा इण्डिया, तभी बढ़ेगा इण्डिया' के नारे को वास्तविक रुप प्रदान करने के लिए दस सरकारी और दस निजी संस्थाओं को विश्व स्तरीय अनुसंधान केन्द्र युक्त शिक्षण संस्थान बनाने का प्रस्ताव भी इस बजट में किया गया। जेटली के इन प्रयासों से भारतीय शिक्षा की तस्वीर निश्चित सुधरेगी।*

**– डॉ. सुभाष शर्मा**

मेरी शुरु से मान्यता रही है कि अगर हम देश के युवाओं को कुशल कारीगर बना सकें तो न सिर्फ देश में बल्कि पूरे विश्व में रोजगार की असंख्य संभावनायें खुल जायेगी। राजग सरकार ने शुरु से ही इस विषय को अपनी प्राथमिकता पर रखा है किन्तु इस बजट में इस

पर विशेष जोर देते हुए राष्ट्रीय बहुकौशल प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही अगले तीन वर्षों में एक करोड़ से अधिक युवाओं को कुशल बनाने का लक्ष्य प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत रखा गया है। इससे ना सिर्फ युवाओं का भविष्य सुरक्षित होगा बल्कि कुशल कारीगरों के मिलने से उद्योगों की उत्पादकता बढ़ेगी, जिससे अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इण्डिया के नारे को अमलीजामा पहनाने के लिए बजट में नेशनल डिजिटल लिट्टरेसी मिशन के लिए 2059 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह मिशन युवाओं में डिजिटल साक्षरता को बढ़ाकर उनको ज्यादा सशक्त व सक्षम बनाने का कार्य करेगा। इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलु यह है कि सिर्फ शहरी ही नहीं बल्कि ग्रामीण युवाओं को भी महत्व दिया गया है। ग्रामीण भारत के लिए अलग से डिजिटल साक्षरता मिशन शुरु करने का फैसला लिया गया है, जिसमें अगले तीन सालों के भीतर तीन करोड़ परिवारों को शामिल किया जायेगा। मेरी नजर में यह योजना ग्रामीण युवाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए गेमचेंजर साबित होने वाली है। इससे सूचना क्रान्ति जो शहरों तक सीमित थी, का लाभ गांव–गांव तक पहुंचेगा। इसके साथ ही ये मिशन इ–गवर्नेंस को बढ़ाने में लाभकारी होगा।

यह बजट एक और कारण से प्रशंसा योग्य है कि इसने इस मान्यता में विश्वास किया है कि युवा उद्यमी देश की तकदीर बदलने में सक्षम है। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने युवा उद्यमियों को सशक्त करने के लिए बजट में लीक से हटकर प्रयोग किये हैं। किसी भी स्टार्टअप को शुरु के पांच वर्षों में से तीन वर्षों तक टैक्स में 100 प्रतिशत की छूट, एक ही दिन में कंपनी रजिस्ट्रेशन की सुविधा, जैसे कदमों से युवा अब ज्यादा विश्वास के साथ उद्यमिता की ओर कदम बढ़ायेगें। यह एक नये भारत के उदय का आरंभ है जिसमें रोजगार मांगने वाले युवा अब रोजगार पैदा करने वाले बनेगें। साल के आरंभ में मोदी ने जब स्टार्टअप इण्डिया योजना की घोषणा की थी, तब शायद ही किसी ने

**विश्व का सबसे युवा देश भारत है, जिसकी 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम है।**

सोचा होगा कि मात्र दो महीने में जेटली इस सपने को साकार करने के लिए इतने बड़े कदम उठायेगें।

अब एक और साहसिक कदम की बात करना चाहूगां जिसमें इस सरकार ने दलित युवाओं के लिए स्वावलंबी उद्यमी बनने का नया मार्ग खोला है। स्टैण्डअप योजना के तहत एससी, एसटी को नये उद्योग लगाने के लिए विशेष सहायता हेतू 500 करोड़ रुपये बजट रखा गया है। इतना ही नहीं, साथ ही बैंक की हर शाखा के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वह कम से कम दो उद्यमियों को सहायता प्रदान करें। सरकार मात्र पूंजी उपलब्ध करवाने तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि दलित उद्यमियों को मार्केट उपलब्ध कराने के लिए सूक्ष्म व लघु उद्योग मंत्रालय में एससी–एसटी केन्द्र खोला जायेगा। यह केन्द्र दलित उद्यमियों के उत्पादों को सरकारी खरीद में शामिल करवाने हेतू उचित सहायता उपलब्ध करवायेगा।

इस कदम से ना केवल दलितों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा बल्कि उनमें स्वावलंबन और स्वाभिमान की भावना का विकास भी करेगा।

विश्व का सबसे युवा देश भारत है, जिसकी 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम है। इस युवा ऊर्जा के सर्वांगीण विकास के क्रम में ये बजट मील का पत्थर साबित होगा। इस बजट से वित्तमंत्री ने भाजपा के वैचारिक आधार अन्तोदय जिसका अर्थ है– समाज के अन्तिम व्यक्ति का उत्थान, को मूर्त रुप देने का प्रयास किया है। युवाओं को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा और रोजगार की देने वाले इस बजट से ना केवल भारत के युवाओं को आगे बढ़ने का असिमित अवसर मिलेगा बल्कि युवा शक्ति के दम पर भारत विश्व की महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर होगा। ❑❑

लेखक रा.प. सदस्य, स्वदेशी जागरण मंच एवं निदेशक, आर्थिक नीति शोध केन्द्र (CEPR) चण्डीगढ़ है।

# भारतीय काल गणना की सार्वभौमिकता व खगोल शुद्धता

**विश्व में प्रचलित** सभी काल गणनाओं में भारतीय तिथियां ही सार्वभौम संदर्भ योग्य दिनक्रम प्रदान करती हैं। इन तिथियों का आरंभ व समाप्ति काल पृथ्वी पर सभी स्थानों पर एक समान होने से उनका संदर्भ सार्वभौम होता है। दूसरी ओर आंग्ल तारीखें मध्य रात्रि से बदलती हैं जिसका (मध्य रात्रि का) समय स्थान विशेष पर अलग–अलग होता है व भिन्न–भिन्न स्थानों पर उसमें 24 घण्टे तक का अंतर आ जाता है। उदाहरणतः भारत व अमरीका में मध्य रात्रि में साढ़े बारह घंटे तक का अंतर होने पर भी हिन्दू कालमान की तिथियों में परिवर्तन तो एक ही समय होता है। लेकिन, तारीख बदलने में सदैव 12 घंटे 30 मिनट तक का अंतर आ जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा के पूर्व एवं पश्चिम में तो तारीखों में सदैव ही एक दिन का अंतर रहता है। भारतीय तिथियों की दृष्टि से यदि अभी ईस्वी सन् 2016 के हिन्दू नववर्ष के प्रथम दिन का ही विचार करें तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा (एकम) का प्रवेश गुरुवार, अप्रैल 7 को भारत में मध्याहन बाद दोपहर, 4 बजकर 54 मिनट पर होगा। इस समय पृथ्वी पर चाहे कहीं रात्रि हो या दिन, अथवा प्रातःकाल हो या सायंकाल, चैत्र शुल्क प्रतिपदा उसी समय, सभी स्थानों पर एक साथ प्रारंभ होगी। इस क्रम में शुक्रवार 8 अप्रैल, को दोपहर 1 बजकर 7 मिनट पर चाहे कहीं दिन हो या रात अथवा प्रभात हो या सायंकाल, प्रतिपदा समाप्त हो कर द्वितीया भी एक साथ ही प्रारंभ होगी। इसी अनुरूप शनिवार, अप्रैल 9, 2016 को प्रातः 9.25 बजे तृतीया प्रारंभ हो जायेगी। संपूर्ण पृथ्वी पर हिन्दू कालमान की तिथियों का परिवर्तन समसामयिक (एक साथ व एक ही समय) होने से ये तिथियां अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ के लिये सर्वाधिक उपयुक्त हैं। यथाः यदि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन भारत से भेजे किसी फेक्स या ईमेल में या अन्य भी किसी घटना के संदर्भ में भारतीय समयानुसार उस दिन, 8 अप्रैल 2016 को प्रातः 7 बजे का समय देना है तो भारत में 7 अप्रैल को अपराह्न 4 बजकर 54 मिनट पर जब प्रतिपदा प्रारंभ होती है उसके 14 घंटे 6 मिनट बाद का समय होने से यदि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के प्रवेशोपरान्त 14 घंटे 6 का संदर्भ दे दिया जाये तो वह सर्वाभौम संदर्भ बन जायेगा, जिसका निर्वचन, व्याख्या या संदर्भ सर्वत्र समान रूप से व तत्काल बोध गम्य हो जायेगा। दूसरी ओर यदि आंग्ल तारीख को संदर्भित कर यह लिखा जाये कि अप्रैल 8, 2016 को भारतीय समयानुसार प्रातः 7 बजे, तो उस समय अमेरिका में 7 अप्रैल सायंकाल 6.30 बजे का समय होगा, इंग्लैंड में 8 अप्रैल का मध्य रात्रि 1.30 का समय होगा, बेकर द्वीप पर 7, अप्रैल का मध्यान्ह 1.30 का समय व थाइलैंड में 8 अप्रैल का प्रातः 10.30 बजे

*पथ्वी पर कहीं से भी चंद्रमा व सूर्य के बीच की कोणीय या चापीय दूरी नापी जाये, वह सदैव एक समान ही दिखलायी देती है या नापने में आती है। अतएवं संपूर्ण भू–मण्डल पर प्रत्येक हिन्दू तिथि एक साथ या एक ही समय परिवर्तित होती है।*

**– डॉ. भगवती प्रकाश शर्मा**

का संदर्भ आयेगा। यह अत्यंत उलझाने वाला होता है।

हिन्दू काल गणना की ये तिथियां, सूर्य व चंद्रमा के बीच प्रति $12^0$ कोणीय दूरी बढ़ने या घटने पर एक–एक कर बदलती हैं। पृथ्वी पर कहीं से भी चन्द्रमा व सूर्य के बीच की कोणीय या चापीय दूरी नापी जाये, वह सदैव एक समान ही दिखलायी देती है या नापने में आती है। अतएवं संपूर्ण भू–मण्डल पर प्रत्येक हिन्दू तिथि एक साथ या एक ही समय परिवर्तित होती है। दूसरी ओर चन्द्रोदय में भी स्थान भेद से एक दिन तक का अंतर होने से अरब हिजरी तिथियों में भी विविध स्थानों की तिथियों व पर्वों या त्यौहारों में एक दिन तक का अंतर आ जाता है। हिन्दू गणनाओं के अंतर्गत संपूर्ण भू–मण्डल पर अमावस्या का आरंभ व अंत एक ही समय होता है, उसमें 1 मिनट का भी अंतर स्थान भेदवश नहीं आता है। तिथियों में अमावस्या को सूर्य व चंद्रमा एक ही रेखांश पर होते हैं। वहां से उनके (सूर्य व चंद्र के) बीच कोणीय अंतर $12^0$ तक होने तक शुक्ल प्रतिपदा रहती है व $12^0$ से $24^0$ होने तक द्वितीया, $24^0$ से $36^0$ कोणीय दूरी होने तक तृतीया व इसी प्रकार $168^0$–$180^0$ के बीच पूर्णिमा व उसके बाद $180^0$–$192^0$ तक कृष्ण प्रतिपदा। पृथ्वी से सूर्य व चंद्र की दूरी इतनी अधिक है कि सूर्य व चंद्रमा के बीच की कोणीय दूरी कहीं से भी नापने पर वह एक समान ही दिखायी देती है।

भारतीय काल गणना में मासों की रचना व नामकरण भी, वर्ष भर में आने वाली 12 पूर्णिमाओं के नक्षत्रों को दृष्टिगत रखकर पूर्ण वैज्ञानिकता के आधार पर किया गया है। यथा चित्रा नक्षत्र में पूर्णिमा वाले मास का नामकरण चैत्र, विशाखा में पूर्णिमा वाले मास का नाम वैशाख, ज्येष्ठा नक्षत्र में पूर्णिमा वाले मास का ज्येष्ठ, उत्तराषाढ़ा में पूर्णिमा वाले मास का आषाढ़, श्रवण नक्षत्र में पूर्णिमा आने पर श्रावण, अश्विनी में पूर्णिमा आने पर अश्विन और इसी प्रकार फाल्गुन पर्यंत बारह मासों के नाम उन मासों की पूर्णिमा वाले दिन के नक्षत्र के अनुसार निर्धारित किये गये हैं। आंग्ल मासों में तो ज्यूलियस सीजर ने एक मास का नाम अपने नाम पर जुलाई कर दिया तो उसके भतीजे अगस्टस ने सम्राट बनने पर 'सेक्सटिनिल' नामक आठवें मास का नाम अपने नाम पर अगस्त कर लिया। जुलाई में 31 दिन होते थे तो उसने भी 'मैं किसी से कम नहीं' के भाव से अगस्त में भी 30 के स्थान पर 31 दिन करवा दिये।

**अयन चलन के कारण ही निरयन ग्रह गणनाओं में मकर सक्रान्ति 22 दिसंबर से 14 जनवरी तक आगे बढ़ गयी है, और उसके बाद 15,16, व 17 जनवरी इसी क्रम में और आगे बढ़ती जायेगी।**

इसके लिये फरवरी में तब 29 दिन होते थे, वे घटा कर 28 करवा दिये। रोमन सम्राट क्लाडियस ने भी मई मास का नाम परिवर्तन करा कर अपने नाम पर क्लाडियस और नीरो ने अप्रैल मास का नाम अपने नाम पर नीरोनियस भी करवा लिया था। लेकिन, ये नाम अधिक दिन नहीं चल पाये और वापस अप्रैल व मई के नाम से ही संबोधित किये जाने लगे। हिन्दू मासों के नाम के प्रणेता ऋषियों ने इन सभी मासों के नाम खगोलीय संयोग के अनुरूप चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आशाढ़, श्रावण, भाद्रपद आदि भी इन मासों की पूर्णिमाओं के नक्षत्रों के अनुसार भी पिछले 1000 वर्षों में तब ही किये, जब इन महीनों की पूर्णिमाएं इन नक्षत्रों में आने लगी थीं। वस्तुतः प्रति 25,765 वर्षों में अयन चलन की एक आवृत्ति पूरी होती है। अयन चलन वस्तुतः पृथ्वी के घूर्णन की धुरी में, अन्य ग्रहों के आकर्षण के कारण आने वाला लघु वृत्ताकार विचलन है, और इसी कारण प्रतिवर्ष बसंत संपात कुछ विकलाओं में पीछे सरकता जाता हैं। अयन चलन के कारण ही निरयन ग्रह गणनाओं में मकर सक्रान्ति 22 दिसंबर से 14 जनवरी तक आगे बढ़ गयी है, और उसके बाद 15,16, व 17 जनवरी इसी क्रम में और आगे बढ़ती जायेगी। पाश्चात्य खगोलज्ञ आरंभ में अयन चलन से अनभिज्ञ थे। लेकिन, अब उन्होंने मान लिया है कि अयन चलन होता है व भारतीयों द्वारा प्रयुक्त अयन चलन का मान खगोल शुद्ध हैं। उस अयन चलन के कारण जब ये पूर्णिमायें चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा आदि मासों में आने लगी तब ही इस खगोलीय क्रम के अनुसार विद्वान ऋषियों ने खगोलीय घटना चक्र के अनुरूप मासों का चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ आदि नामकरण किया है। इससे पूर्व वैदिक काल में चैत्र, वैशाख आदि मासों के नाम मधु, माधव, शुक्र, नभ, नभस्य, इश, ऊर्जा, सह, सहस्य, तप, तपस्या आदि प्रचलित थे। इसीलिये प्राचीन यजुर्वेद वाजसानेयी संहिता और तैत्तिरीय संहिता आदि में मासों के यही नाम मधु माधव आदि मिलते हैं। यही कारण है कि रामचरित मानस में भी चैत्र मास में राम नवमी के दिन भगवान राम के जन्म के मास का नाम 'मधु' मास लिखा है यथाः ''नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पच्छ अभिजित हरि प्रीता'' इस चौपाई में चैत्र मास के स्थान पर वैदिक कालीन व रामायण कालीन मास–नाम मधु मास लिखा है।

चूंकि श्रीराम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। भारतीय काल गणनानुसार

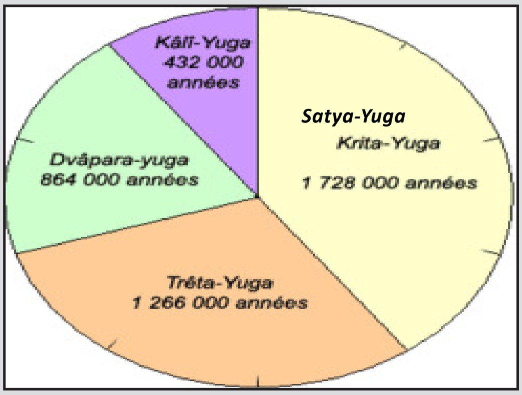


**भारतीय काल गणनानुसार वर्तमान में 4,32000 वर्षमान के कलियुग के 5115 वर्ष हुये हैं**

वर्तमान में 4,32000 वर्षमान के कलियुग के 5115 वर्ष हुये हैं और उसके पूर्व 8,64,000 वर्षमान का द्वापर युग व्यतीत हुआ था, जिसके अन्त में और आज से 5240 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। द्वापर युग के पूर्व 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग व्यतीत हुआ है, जिसके अन्तिम चरण में श्रीराम का जन्म हुआ है। इस प्रकार त्रेता युग जो 8,69,115 वर्ष पूर्व समाप्त हो गया था। इसे लेकर आधुनिक इतिहासकार आक्षेप करते हैं कि, वर्तमान सृष्टि व सभ्यता ही इतनी प्राचीन नहीं है। महाभारत काल को वे ईसा से मात्र 1000 वर्ष प्राचीन व रामायण काल को वे ईसा से 1500 वर्ष प्राचीन ही ठहराते हैं। जबकि रामायण में वाल्मिकी जी ने जिन 4 दाँत वाले हाथियों का वर्णन किया है। वैसे चार दाँत वाले हाथियों के 15–20 लाख वर्ष प्राचीन जीवाश्म व कंकाल आज बड़ी संख्या में उत्तरी अमेरिका, फ्रासं, जर्मनी, रूस, अफ्रीका व श्रीलंका, पाकिस्तान आदि में आज मिल रहे हैं। पुरातात्विक उत्खननों के आधार पर आधुनिक पुरातत्वविद कहते हैं कि पृथ्वी पर ये 4 दाँत वाले हाथी 2.5 करोड़ वर्ष पहले से होते आये हैं और वे 10 लाख वर्ष पूर्व पूरी तरह से विलुप्त हो गये थे। यदि चार दाँत वाले हाथी 10 लाख वर्ष पूर्व विलुप्त हो गये, रामायण में उनका वर्णन आता है और हमारी काल गणनानुसार त्रेता युग, जिसमें श्री राम का जन्म हुआ था, उसकी अवधि 21,25,115 वर्षों से लेकर 8,69,115 वर्षों के बीच रही है, तो यह श्रीराम, श्रीमद्वाल्मिकीय रामायण और त्रेता युग के काल–मान का सर्वाधिक सटीक प्रमाणीकरण है। चूंकि चार दाँत वाले हाथी 10 लाख वर्ष पूर्व ही विलुप्त हो गये थे। इसलिये महाभारत में कही भी 4 दाँत वाले हाथियों का संदर्भ ही नहीं है। लेकिन, जैसी हमारी मान्यता है कि द्वापर युग के अन्त में 5240 वर्ष पूर्व श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था, तदनुरूप श्रीकृष्ण की द्वारिका के पुरातात्विक अवशेष आज समुद्र में 120 फीट नीचे जल में इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनेग्राफी ने खोज लिये हैं। वे रेडियो कार्बन काल निर्धारण प्रक्रिया में 5000 वर्ष पुराने सिद्ध हुये हैं। उनमें प्राचीन द्वारिका की समुद्र से रक्षार्थ बनायी 30 फीट चौड़ी शहरकोट (नगररक्षा प्राचीर) के अवशेष और उस समय के भवनों, बर्तनों आदि के महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं, जो 5000 वर्ष पुराने सिद्ध हुये हैं। इसके अतिरिक्त वहाँ खंभात में 7500 वर्ष प्राचीन बंदरगाह के भी अवशेष मिले हैं, जिनमें जहाजों के लिये 150 से अधिक लंगर, बंदरगाह की जेटी आदि प्रमुख हैं। पुरातात्विक अवशेषों की दृष्टि से अभी तमिलनाडू में कोडूमनाल में जिस 2500 वर्ष प्राचीन औद्योगिक नगर के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, वहाँ तो उच्च गुणवत्ता का लोहा व इस्पात बनाने के उद्योगों, वस्त्रोद्योग व रत्न प्रविघेंयन आदि के महानुमाप उत्पादन के प्रचुर प्रमाण मिले हैं। वहाँ पर पश्चिम के रोम (इटली) व मिश्र के और पूर्व में थाइलैण्ड के सिक्के भी मिले हैं। अर्थात ढ़ाई से तीन हजार वर्ष पूर्व हमारा व्यापार वहाँ तक फैला हुआ था। वहाँ उत्तर भारत व दक्षिण भारत के नामों के संयुक्त लेख भी मिले हैं, वे आर्य–द्रविड़ विभाजन को निर्मूल सिद्ध करते हैं। आज जिन यूरो विट्रीफाइड टाइलों का विकास हम 21 वीं सदी में यूरोप में हुआ मानते हैं, वैसे इस्पात उत्पादन के 2500 वर्ष पुराने विट्रीफाइड क्रुसिबल (कड़ाह) भी कोडूमनाल में मिले हैं। इनके साथ ही वहाँ पद्मासन की अवस्था में मिले प्राचीन 2500 वर्ष पुराने नर कंकाल उस काल में योग के प्रचुर चलन का भी प्रमाण देते हैं। आज हमारे प्राचीन शास्त्र, वाल्मिकी रामायण में वर्णित 10 लाख वर्ष प्राचीन चार दाँत वाले हाथियों के वर्णनों से लेकर कोडूमनाल तक के औद्योगिक अवशेषों के अध्ययन साथ–साथ कोडूमनाल की तमिल ब्राह्मी लिपि से लेकर सिन्धुघाटी सभ्यता में मिली लिपि और दक्षिण अमेरिका में पेरू, चिली व बोलिविया के प्राचीन शिलालेखों की लिपि में यत्किंचित साम्यता के जो प्रारम्भिक अध्ययन हुये हैं उन्हें भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता हैं। इनसें हम वैदिक, पौराणिक, रामायण कालीन, महाभारत कालीन और उसके परवर्ती कालीन इतिहास पर अधिक प्रकाश डाल सकेंगे। ढ़ाई हजार वर्ष पुराने कोडूमनाल की तमिल ब्राह्मी लिपि व सिन्धु घाटी की 5000 वर्ष पुरानी लिपि में संबंध तो महाभारत काल से हमारी सभ्यता की निरंतरता को भी प्रतिपादित करेगा।

पुनः हिन्दू काल गणना की वैज्ञानिकता पर आते हुये यदि मासों पर विचार करें तो चान्द्र मासों के साथ–साथ हमारे प्राचीन ऋषियों ने राशियों के नाम पर सौर मासों यथा संक्रान्ति से

संक्रान्ति पर्यंत राशि, अंश, कला व विकला में सौर मास व मास के दिनक्रम के अंतर्गत 24–24 मिनट की घटियों तक के समय तक का अंकन एक साथ करने का की जो परंपरा विकसित की थी वह आज की आंग्ल दिनांक से भी अधिक व्यवस्थित व सूक्ष्म पद्धति रही है। यह अंकन आज भी पंचागों व जन्म पत्रिकाओं में महादशा व अंतर्दशा के आरंभ व समाप्ति काल को इंगित करने हेतु किया जाता है। पुनः इन सौर मासों से चान्द्र मासों का संतुलन करने के साथ–साथ करोड़ों वर्ष बाद भी चान्द्र मासों का ऋतु चक्र से कुसमायोजन या पृथक्करण नहीं हो जाये, इस हेतु संक्रान्ति रहित मास को 'अधिक–मास' की संज्ञा देकर प्रति तीन वर्ष में एक अधिक मास का प्रावधान कर दिया। इससे हमारे सभी पर्व व त्यौहार एवं वर्षों का प्रारंभ करोड़ों वर्षों से सदैव उसी ऋतु में होता रहा है व आगे भी होता रहेगा। अरब हिजरी वर्ष मान भी 354 दिन का ही होने से प्रति तीन वर्ष में हिजरी नववर्ष व सभी त्यौहार लगभग, एक माह आगे बढ़ जाते हैं और 9 वर्ष में एक ऋतु से दूसरी ऋतु में चले जाते हैं। इस प्रकार 1393 सौर वर्षों में हिजरी वर्ष 1435 आ गया है।

पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करती है, उसकी सटीक परिभ्रमण गति को भी पृथ्वी की दैनिन्दिन गति के रूप में आर्य भट्ट ने 2000 वर्ष पूर्व आर्यभट्टीय में दे दिया था। अर्थात् प्राचीनकाल से ही भारतीयों को यह ज्ञान था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी की गति के संबंध में ऐलरेय ब्राह्मण में भी लिखा है कि सूर्य न उदित होता है और न अस्त होता है। सूर्य पृथ्वी के एक भाग को आलोकित करता है, तब दूसरे में व जब दूसरे को आलोकित करता है, तब पहले में अंधकार होता हैं। यहीं नहीं पुराणों में वर्णित प्रमुख पांच विषयों सर्ग (सृष्टि) प्रति सर्ग (प्रलय) आदि में सर्ग या सृष्टि खण्ड में यह भी वर्णन आता है कि सूर्य भी एक महा सूर्य की परिक्रमा 49 हजार योजन प्रति–घटी की गति से कर रहा है। आधुनिक खगोलवेत्ताओं के अनुसार, सूर्य हमारी इस आकाश गंगा में एक अति शाक्तिशाली कृष्ण विवर (Super massive black hole) की लगभग 7.45 लाख किमी. प्रति घण्टा की गति से परिक्रमा कर रहा है और 21 करोड़ 60 लाख वर्ष में वह उसकी एक परिक्रमा पूरी करता है। इतनी अवधि में 50 चतुर्युगियाँ व्यतीत हो जाती हैं। हमारी पौराणिक काल गणनाओं के अनुसार 43.20 लाख वर्ष में एक चतुर्युगी पूरी होती है, जिसमें 4.32 लाख वर्ष का कलियुग, 8.64 लाख वर्ष का द्वापर, 12.96 लाख वर्ष का त्रेता और 17.28 लाख वर्ष का सतयुग होता हैं। इकहत्तर चतुर्युगियों का एक मन्वन्तर और 14 मन्वन्तर अर्थात् 1000 चतुर्युगियों का ब्रह्मा जी का एक दिन, ऐसे 360 दिन का ब्रह्मा जी का एक वर्ष व 100 वर्ष की एक ब्रह्मा जी की आयु होती है। एक ब्रह्मा के बाद दूसरे ब्रह्मा जन्म लेते है व सृष्टिक्रम चलता रहता है। इस क्रम में हमारी आकाशगंगा की, इस सृष्टि के ब्रह्माजी के 50वें वर्ष के श्वेतवाराह कल्प के वैवस्वत मन्वन्तर का 28वां कलियुग चल रहा है। तदानुसार हमारी इस आकाशगंगा की वर्तमान सृष्टि का यह 195,58,85,115वां वर्ष पूर्ण हो गया है। हमारे पुराणों के अनुसार हमारी इस सृष्टि से युक्त यह जो आकाश गंगा अर्थात तारा मण्डल हमें दिखायी देता है वैसे असंख्य तारा मण्डल या आकाश–गंगायें अनन्त ब्रह्माण्ड में विस्तीर्ण हैं। देवी भागवत में आद्या शक्ति द्वारा त्रिदेवों को या रामायण में भगवान राम द्वारा काकभुशुण्डि को मन की गति से भ्रमण कराते हुये एक के बाद एक जिन आकाश गंगाओं का कहीं अन्त नहीं होने के दिग्दर्शन का वर्णन किया गया है। इन वृत्तान्तों की अब वैज्ञानिक पुष्टि हो रही हैं कि ब्रह्माण्ड में 100 अरब से अधिक आकाशगंगायें हैं, एक आकाश गंगा का विस्तार लगभग 1,00,000 प्रकाश वर्ष है। दो आकाश गंगाओं के बीच औसत दूरी 25 लाख प्रकाश वर्ष है। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्माण्ड और भी अनन्त हो सकता है अभी 46 अरब प्रकाश वर्ष पर्यन्त आकाश गंगाओं के विस्तार के प्रमाण मिल चुके हैं। प्रकाश 1.86 मील प्रति सेकण्ड की गति से एक वर्ष में 60 खरब मील तय करता हैं। ऐसे 60 खरब मील का एक प्रकाश वर्ष और ऐसे 46 अरब प्रकाश वर्ष पर्यन्त ब्रह्माण्ड के विस्तार के प्रमाण से अन्त रहित (नेति=न+इति) ब्रह्माण्ड में अनन्त आकाश गंगाओं का पौराणिक वर्णन हिन्दु काल गणनाओं एवं ब्रह्मण्ड के विवरणों की पूर्ण वैज्ञानिकता को सिद्ध करता है। ❑❑

**वैज्ञानिक पुष्टि हो रही हैं कि ब्रह्माण्ड में 100 अरब से अधिक आकाशगंगायें हैं, एक आकाश गंगा का विस्तार लगभग 1,00,000 प्रकाश वर्ष है।**

# देश की अखंडता को चुनौती

**जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय** (जेएनयू) में कुछ छात्रों ने देश को टुकड़े–टुकड़े करने और उसकी बर्बादी के जिस तरह के नारे अपने एक कार्यक्रम में लगाये, वह कोई साधारण घटना नहीं है। यह देश की एकता और अखंडता को चुनौती देने की कोशिश है। कुछ पड़ोसी देश जिस तरह भारत के खिलाफ षडयंत्र कर रहे हैं, यह अब कोई छिपी बात नहीं है। पाकिस्तान ने आतंकवाद को अपनी विदेश नीति का हथियार बना रखा है और जम्मू–कश्मीर में लगातार उसके आतंकवादी घुसपैठ करने की कोशिशें करते रहते हैं और सीमा सुरक्षा बलों से उनकी मुठभेड़ आये दिन हुआ करती है। चीन ने नेपाल में अपनी कारगुजारी दिखाने के बाद अब वह भारत को भी अपने निशाने पर ले रहा है। देश में चौतरफा हो रही आतंकी और नक्सली घटनाओं के पीछे पाकिस्तान और चीन की भूमिका अब कोई छिपी बात नहीं है। देश की सरकार आतंकवादी और नक्सली हिंसा की घटनाओं का पूरी ताकत के साथ जवाब भी दे रही है।

लेकिन चिंता और दुख की बात है देश की सत्ता से बेदखल हो चुके कुछ दल और उसके नेता देश विरोधी गतिविधियों को जिस तरह से भड़का रहे हैं वह देश की एकता और अखंडता के लिए चुनौती बनती जा रही है। यह गंभीर मामला है और सारा देश यह देख रहा है कि कुछ राजनीतिक दलों के नेता देश में जिस तरह से अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उससे हमारे पड़ोसी देशों को ही मदद मिल रही है। ऐसी स्थिति में उन्हें अपने मंसूबे पूरे करने की जमीन तैयार दिखायी दे रही है। इसलिए इस पर विचार करना जरूरी है कि आज देश की एकता और अखंडता के लिए कुछ दल किस तरह से खतरा पैदा कर रहे हैं।

लगभग सवा सौ साल पुरानी कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता केंद्र की सत्ता से बेदखल होने के बाद जिस तरह की राजनीति पर उतारू हो गये हैं, उसकी आजाद भारत में कोई मिसाल नहीं मिलती है। एक तरफ हमारी सेना के जवान देश के लिए जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी

*देश में चौतरफा हो रही आतंकी और नक्सली घटनाओं के पीछे पाकिस्तान और चीन की भूमिका अब कोई छिपी बात नहीं है। देश की सरकार आतंकवादी और नक्सली हिंसा की घटनाओं का पूरी ताकत के साथ जवाब भी दे रही है।*

**– निरंकार सिंह**

आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो रहे हैं तो दूसरी तरफ दिल्ली की जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में कुछ छात्रों का गिरोह देश के टुकड़े–टुकड़े और बर्बादी के खुलेआम नारा लगाता है और जम्मू कश्मीर की आजादी की बात करता है। वह हमारे सुरक्षा सैनिकों की मौत पर जश्न मनाता है और अफजल गुरू के समर्थन में नारे लगाता है। ऐसे ही नारे तो जम्मू–कश्मीर में अलगाववादी और पाकिस्तान में हाफिज सईद के समर्थक लगाते हैं। ऐसे छात्रों के समर्थन में जाकर कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? कम्युनिस्टों और माओवादियों की रीति–नीति के बारे में तो सभी को पता है। वामपंथियों के समर्थकों ने तो पश्चिम बंगाल और केरल में अपने राजनीतिक विरोधियों की हत्या करने तक में भी संकोच नहीं किया है। कम्युनिस्टों की भूमिका तो देश की स्वाधीनता के संघर्ष में संदिग्ध रही है। पर कांग्रेस का इतिहास तो आजादी की लड़ाई का रहा है, उसके नेता इतने दिशाहीन हो जायेंगे यह तो किसी ने सोचा भी नहीं था। जेएनयू के इन देश विरोधी छात्रों के खिलाफ पूर्व सैनिकों ने भी दिल्ली में प्रदर्शन किया था। राहुल गांधी यदि वहां गये होते तो उनका सम्मान और जनाधार दोनों बढ़ता लेकिन जेएनयू में जाकर देश के खिलाफ नारे लगाने वाले छात्रों का समर्थन करके वह क्या हासिल करना चाहते हैं? यदि वे इसके माध्यम से अल्पसंख्यकों का वोट हासिल करना चाहते हैं तो यह एक खतरनाक दांव है और देश के लिए घातक राजनीति है। यह देश जितना हिन्दुओं का है उतना ही अल्पसंख्यकों का भी है और कोई भी वर्ग अलगाववादियों का समर्थन नहीं कर सकता है। कांग्रेस को यह नहीं भूलना चाहिए कि उनकी ही सरकार के कार्यकाल में अफजल गुरू को फांसी की सजा मिली थी। अब उसके ही नेता इस पर सवाल उठा रहे है। इस संबंध में पूर्व गृह मंत्री पी. चिदम्बरम् का ताजा बयान आश्चर्यजनक है।

हैदराबाद के केंद्रीय विश्वविद्यालय से निलंबित छात्र रोहित बेमुला की आत्महत्या के दुखद मामले को भी राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से तिल को ताड़ बनाकर छात्रों को भड़काने का काम किया है वह किसी जिम्मेदार नेता का काम नहीं हो सकता है। यहां बताना जरूरी है कि इस दलित छात्र का भी कुछ राजनीतिज्ञों ने आतंकवादी याकूब मेमन की फांसी के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए जिस तरह से इस्तेमाल किया वह अलग जांच का विषय है। इन दोनों नेताओं ने हैदराबाद जाकर रोहित की आत्महत्या के विरोध में आयोजित छात्रों के प्रदर्शन में भाग लिया था। इतना ही नहीं दिल्ली में कुछ छात्रों ने जब प्रदर्शन किया तो वहां भी राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंच गये। केजरीवाल की तो पूरी राजनीति ही नरेंद्र मोदी के विरोध के ही इर्द–गिर्द घूम रही है। पहले ही दिन से उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। दिल्ली में वह छात्रों के प्रदर्शन में कहते हैं कि– 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों से पंगा न ले। छात्र खड़े हो गये तो उनकी कुर्सी कब हिल जायेगी पता नहीं चलेगा।' उधर राहुल गांधी के अनुसार– 'आज पूरे देश में युवाओं की आवाज दबायी जा रही है।' संघ और भाजपा के लोग चाहते हैं कि देशवासियों की एक ही सोच और एक ही भाषा हो। पर यह भारत है जहां कुछ लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर प्रधानमंत्री तक गाली देते हैं और उन्हें हटाने के लिए पाकिस्तान से सहयोग मांगते हैं।

**दुनिया भर में अनुसंधान, विकास और खोज का काम विश्वविद्यालयों में होता है लेकिन हमारे देश के विश्वविद्यालय जिस घटिया राजनीति के केंद्र बन गये हैं, उसकी मिसाल खोजनी मुश्किल है।**

विपक्षी दल होने के कारण बेशक आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कटु आलोचना कर सकते है और भाजपा एवं संघ के खिलाफ भी दिल खोलकर अपनी भड़ास निकाल सकते हैं। लेकिन देश की एकता और अखंडता को चुनौती देने वाले छात्रों का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर आप उनका समर्थन नहीं कर सकते हैं। अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए छात्रों का राजनीतिक इस्तेमाल भी छात्रों और देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ ही कहा जायेगा। देश में अनेक राज्यों में हजारों दलितों और वंचितों के साथ अन्याय होता रहा है तब आप ने अपनी आवाज क्यों नहीं उठायी। जाहिर है जहां वोट बैंक की राजनीति नहीं हो सकती थी वहां आप ने खामोश रहने में ही अपनी भलाई समझी है। लेकिन छात्रों को अपनी राजनीति का हथियार बनाना चाहते हैं। इसीलिए दो–दो बार हैदराबाद गये और फिर दिल्ली में भी उनके प्रदर्शन में शामिल हो गये। जनता देख रही है कि देश के विकास में कौन बाधा पैदा कर रहा है और कौन अराजकता फैला रहा है।

दुनिया भर में अनुसंधान, विकास और खोज का काम विश्वविद्यालयों में होता है लेकिन हमारे देश के विश्वविद्यालय जिस घटिया राजनीति के केंद्र बन गये हैं, उसकी मिसाल खोजनी मुश्किल है। उन पर खर्च तो बहुत हो रहा है पर हासिल कुछ नहीं

हो रहा है। यही कारण है कि दुनिया के टाप 200 विश्वविद्यालयों में हमारे देश का एक भी विश्वविद्यालय शामिल नहीं है। नट–बोल्ट बनाने से लेकर पॉवर प्लांट तक की तकनीक के मामले में हम आज भी विदेशी कंपनियों पर निर्भर हैं। सुई से लेकर पेन तक सारे आविष्कार पश्चिमी देशों के वैज्ञानिकों ने ही किये हैं। उसमें किसी भारतीय का नाम नहीं मिलता है। सारी टेक्नालॉजी पश्चिम से आयी है। अगर आप उस टेक्नालॉजी में दुनिया के साथ खड़े होना चाहते हैं तो अपने विश्वविद्यालय को राजनीति का अड्डा मत बनने दीजिए, वहां पठन–पाठन का वातावरण बनाइए।

**दुनिया के टॉप २०० विश्वविद्यालयों में हमारे देश का एक भी विश्वविद्यालय शामिल नहीं है। नट-बोल्ट बनाने से लेकर पॉवर प्लांट तक की तकनीक के मामले में हम आज भी विदेशी कंपनियों पर निर्भर हैं।**

देश के छात्रों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश की प्रतिभा में कैसे चार चांद लगायें। कैसे वह नये–नये अनुसंधान और आविष्कार करें कि उनका देश आगे बढ़ सके। इसके लिए देश उनको 25 वर्ष तक भोजन, कपड़े की सारी व्यवस्था कर रहा है। उनसे देश और कोई अपेक्षा नहीं करता। उनसे सिर्फ एक ही अपेक्षा है कि वह देश की प्रतिभा को ऊंचाईयों पर ले जायें। पूरा देश उनके लिए मेहनत करके इस आशा से 25 वर्ष सुरक्षित कर रहा है। लेकिन राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी को हिलायें और झंडे लेकर उनके पीछे जय–जयकार करें। ऐसा करके वे छात्रों और देश का बहुत नुकसान कर रहे हैं। छात्रों के लिए जरूरी है कि पहले वे राजनीति को ठीक से समझे और जब 25 साल बाद राजनीति में आयें तो उन्हे कोई दो कौड़ी का नेता राजनीति में धोखा न दे सके। लेकिन जो सत्ता में नहीं है अथवा और बड़ी सत्ता पाना चाहते हैं वे उनका राजनीतिक इस्तेमाल करने पर तुले हुए हैं फिर इसके लिए वे कुछ भी करने को तैयार हैं। देश के छात्रों और युवकों के सामने बड़ा सवाल है कि देश की राजनीतिक चेतना को कैसे उन्नत किया जाये। एक हजार साल तक गुलाम रहने के कारण हमने राजनीतिक बोध खो दिया है। इसलिए वह किसी कें भी पीछे झंडा और डंडा लेकर खड़ा हो जाता है और राजनीतिक उसका शोषण करते हैं। लेकिन अब यह नहीं चलेगा क्योंकि सारे देश की जिंदगी छात्रों और युवकों के निर्णय पर निर्भर है और हम निर्णय लेने में कितने बुद्धिमान हैं, इस पर देश का भविष्य निर्भर है। इसलिए कुछ सिरफिरे लोगों की राजनीति का माध्यम बनने से छात्रों को बचना होगा क्योंकि वे इस देश के भविष्य हैं। उनका आक्रोश विवेकसम्मत होना चाहिए। कुछ भटके हुए छात्रों और युवकों के साथ खड़े होकर वे अपने भविष्य को तो नहीं बिगाड़ रहे हैं, यह उन्हें सोचना चाहिए। सारी राजनीति देश को खण्ड–खण्ड बनाये रखने पर जीवित है और वे कहते हैं कि देश भक्ति हमारे खून में है और राष्ट्र की एकता का पाठ हमें न पढ़ाया जाये। लेकिन पूरे देश में अराजकता फैलाकर आप क्या हासिल करना चाहते हैं? अब तो हरियाणा के जाट आरक्षण के हिंसक आंदोलन को भड़काने में भी एक पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार की भूमिका उजागर हो रही है। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस के कुछ नेता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री मानने को ही तैयार नही है और उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिशें कर रहे है। इस तरह कांग्रेस कभी भी जनता में अपना जनाधार नही बढ़ा पायेगी। यह सोचते हुये बढ़ा अजीब से लगता है कि एक राष्ट्रीय दल सत्ता गवाने के बाद इतना पतित हो जायेगा कि अराजक तत्वों का भी समर्थन करने लगेगा। ❑❑

*लेखक हिन्दी विश्वकोश के सहायक संपादक रह चुके हैं। आज कल स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य कर रहे हैं।*


## :: सूचना ::

**स्वदेशी पत्रिका सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।**

**संपादक, स्वदेशी पत्रिका**

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

# भारत विरोध का बनता केंद्र, जेएनयू

**यह एक यक्ष प्रश्न** है कि इतने बड़े विचारकों, विश्व राजनीति–अर्थनीति की गहरी समझ, तमाम नेताओं की अप्रतिम ईमानदारी और विचारधारा के प्रति समर्पण के किस्सों के बावजूद भारत का वामपंथी आंदोलन क्यों जनता के बीच स्वीकृति नहीं पा सका? अब लगता है, भारत की महान जनता इन राष्ट्रद्रोहियों को पहले से ही पहचानती थी, इसलिए इन्हें इनकी मौत मरने दिया। जो हर बार गलती करें और उसे ऐतिहासिक भूल बताएं, वही वामपंथी हैं। वामपंथी वे हैं जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे राष्ट्रनायक को 'तोजो का कुत्ता' बताएं, वे वही हैं जो चीन के साथ हुए युद्ध में भारत विरोध में खड़े रहे। क्योंकि चीन के चेयरमैन माओ उनके भी चेयरमेन थे। वे ही हैं जो आपातकाल के पक्ष में खड़े रहे। वे ही हैं जो अंग्रेजों के मुखबिर बने और आज भी उनके बिगड़े शहजादे (माओवादी) जंगलों में आदिवासियों का जीवन नरक बना रहे हैं।

### देश तोड़ने की दुआएं कौन कर रहे है

अगर जेएनयू परिसर में वे 'पाकिस्तान जिंदाबाद' करते नजर आ रहे हैं, तो इसमें नया क्या है? उनकी बदहवासी समझी जा सकती है। सब कुछ हाथ से निकलता देख, अब सरकारी पैसे पर पल रहे जेएनयू के कुछ बुद्धिधारी इस इंतजाम में लगे हैं कि आईएसआई (पाकिस्तान) उनके खर्चे उठा ले। जब तक जेएनयू में भारत विरोधी नारे लगाने वाली ताकतें हैं, देश के दुश्मनों को हमारे मासूम लोगों को कत्ल करने में दिक्कत क्या है? हमारा खून बहे, हमारा देश टूटे यही भारतीय वामपंथ का छुपा हुआ एजेंडा है। हमारी सुरक्षा एजेंसियां देश में आतंकियों के मददगार स्लीपर सेल की तलाश कर रही हैं, इसकी ज्यादा बड़ी जगह जेएनयू है। वहां भी नजर डालिए।

### सरकारी पैसे पर राष्ट्रद्रोह की विषवेल

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय एक ऐसी जगह है, जहां सरकारी पैसे से राष्ट्रद्रोह

*जिस देश ने आपको सांसद, विधायक, मंत्री और प्रोफेसर बनाया। लाखों की तनख्वाहें देकर आपके सपनों में रंग भरे, आपने उस देश के लिए क्या किया? आजादी–आप किससे चाहते हैं? इस मुल्क से आजादी, जिसने आपको एक बेहतर जिंदगी दी।*
– **संजय द्विवेदी**

के बीज बोए जाते हैं। यहां ये घटनाएं पहली बार नहीं हुयी हैं। ये वे लोग हैं नक्सलियों द्वारा हमारे वीर सिपाहियों की हत्या पर खुशियां मनाते हैं। अपनी नाक के नीचे भारतीय राज्य अरसे से यह सब कुछ होने दे रहा है, यह आश्चर्य की बात है। इस बार भी घटना के बाद माफी मांग कर अलग हो जाने के बजाए, जिस बेशर्मी से वामपंथी दलों के नेता मैदान में उतरकर एक राष्ट्रद्रोही गतिविधि का समर्थन कर रहे हैं, वह बात बताती है, उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। यह कहना कि जेएनयू को बदनाम किया जा रहा है, ठीक नहीं है। गांधी हत्या की एक घटना के लिए आजतक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लांछित करने वाली शक्तियां क्यों अपने लिए छूट चाहती हैं? जबकि अदालतों ने भी गांधी हत्या के आरोप से संघ को मुक्त कर दिया है। टीवी बहसों को देखें तो अपने गलत काम पर पछतावे के बजाए वामपंथी मित्र भाजपा और संघ के बारे में बोलने लगते हैं। भारत को तोड़ने और खंडित करने के नारे लगाने वाले और 'इंडिया गो बैक' जैसी आवाजें लगाने वाले किस तरह की मानसिकता में रचे बसे हैं, इसे समझा जा सकता है। देश तोड़ने की दुआ करने वालों को पहचानना जरूरी है।

### राहुल जी, आप वहां क्या कर रहे है

वामपंथी मित्रों की बेबसी, मजबूरी और बदहवासी समझी जा सकती है, किंतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसी जिम्मेदार पार्टी के नेता राहुल गांधी का रवैया समझ से परे है। कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय आंदोलन का अतीत और उसके नेताओं का राष्ट्र की रक्षा के लिए बलिदान लगता है राहुल जी भूल गए हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि वे जाकर देशद्रोहियों के पाले में खड़े हो जाएं? उनकी पं. नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री राजीव गांधी की विरासत का यह अपमान है। इनमें से दो ने तो

अपने प्राण भी इस राष्ट्र की रक्षा के लिए निछावर कर दिए। ऐसे परिवार का अंध मोदी विरोध या भाजपा विरोध में इस स्तर पर उतर जाना चिंता में डालता है। पहले दो दिन कांग्रेस ने जिस तरह की राष्ट्रवादी लाइन ली, उस पर तीसरे दिन जेएनयू जाकर राहुल जी ने पानी फेर दिया। जेएनयू जिस तरह के नारे लगे उसके पक्ष में राहुल जी का खड़ा होना बहुत दुख की बात है। वे कांग्रेस जैसी गंभीर और जिम्मेदार पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उन्हें यह सोचना होगा कि भाजपा और नरेंद्र मोदी का विरोध करते–करते कहीं वे देशद्रोहियों के एजेंडे पर तो नहीं जा रहे हैं। उन्हें और कांग्रेस पार्टी को यह भी ख्याल रखना होगा कि किसी दल और नेता से बड़ा है, देश और उसकी अस्मिता। देश की संप्रभुता को चुनौती दे रही ताकतों से किसी भी तरह की सहानुभूति रखना राहुल जी और उनकी पार्टी के लिए ठीक नहीं है। जेएनयू की घटना को लेकर पूरे देश में गुस्सा है, ऐसे समूहों के साथ अपने आप को चिन्हित कराना, कांग्रेस की परंपरा और उसके सिद्धांतों के खिलाफ है।

**पहले दो दिन कांग्रेस ने जिस तरह की राष्ट्रवादी लाइन ली, उस पर तीसरे दिन जेएनयू जाकर राहुल ने पानी फेर दिया।**

### अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर

कौन सा देश होगा जो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर खुद को तोड़ने की नारेबाजी को प्रोत्साहन देगा। राष्ट्र के खिलाफ षडयंत्र और देशद्रोहियों की याद में कार्यक्रम करने वालों के साथ जो आज खड़े हैं, वे साधारण लोग नहीं हैं। जिस देश ने आपको सांसद, विधायक, मंत्री और प्रोफेसर बनाया। लाखों की तनख्वाहें देकर आपके सपनों में रंग भरे, आपने उस देश के लिए क्या किया? आजादी–आप किससे चाहते हैं? इस मुल्क से आजादी, जिसने आपको एक बेहतर जिंदगी दी। अन्याय और अत्याचार से मुक्ति दिलाने की आपकी यात्रा क्यों गांव–गरीब और मैदानों तक नहीं पहुंचती? अपने ही रचे जेएनयू जैसे स्वर्ग में शराब की बोतलों और सिगरेट की घुंओं में 'क्रांति' करना बहुत आसान है किंतु जमीन पर उतर कर आम लोगों के लिए संघर्ष करना बहुत कठिन है। हिंदुस्तान के आम लोग पढ़े–लिखे लोगों को बहुत उम्मीदों से देखते हैं कि उनकी शिक्षा कभी उनकी जिंदगी में बदलाव लाने का कारण बनेगी। किंतु आपके सपने तो इस देश को तोड़ने के हैं। समाज को तोड़ने के हैं। समाज में तनाव और वर्ग संघर्ष की स्थितियां पैदा कर एक ऐसा वातावरण

बनाने पर आपका जोर है ताकि लोगों की आस्था लोकतंत्र से, सरकार से और प्रशासनिक तंत्र से उठ जाए। विदेशी विचारों से संचालित और विदेशी पैसों पर पलने वालों की मजबूरी तो समझी जा सकती है। किंतु भारत के आम लोगों के टैक्स के पैसों से एक महान संस्था में पढ़कर इस देश के सवालों से टकराने के बजाए, आप देश से टकराएंगें तो आपका सिर ही फूटेगा।

जेएनयू जैसी बड़ी और महान संस्था का नाम किसी शोधकार्य और अकादमिक उपलब्धि के लिए चर्चा में आए तो बेहतर होगा, अच्छा होगा कि ऐसे प्रदर्शनों–कार्यक्रमों के लिए राजनीतिक दल या समूह जंतर–मंतर, इंडिया गेट, राजधाट और रामलीला मैदान जैसी जगहें चुनें। शिक्षा परिसरों में ऐसी घटनाओं से पठन–पाठन का वातावरण तो बिगड़ता ही है, तनाव पसरता है, जो ठीक नहीं है। इससे

**देश तोड़क गतिविधियों और राष्ट्र विरोधी आचरण की आजादी यह देश किसी को नहीं दे सकता। आप चाहे जो भी हों।**

विश्वविद्यालय को नाहक की बदनामी तो मिलती ही है, और वह एक खास नजर से देखा जाने लगता है। अपने विश्वविद्यालय के बचाने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी शायद वहां के अध्यापकों और छात्रों की ही है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना ही, इस बार मिली बदनामी का सबसे बड़ा इलाज है।

एक लोकतंत्र में होते हुए आपकी सांसें घुट रही हैं, तो क्या माओ के राज में, तालिबानों और आईएस के राज में आपको चौन मिलेगा? सच तो यह है कि आप बैचेन आत्माएं हैं, जिनका विचार ही है भारत विरोध, भारत द्वेष, लोकतंत्र का विरोध। आपका सपना है एक कमजोर और बेचारा भारत। एक टूटा हुआ, खंड–खंड भारत। ये सपने आप दिन में भी देखते हैं, ये ही आपके नारे बनकर फूटते हैं। पर भूल जाइए, ये सपना कभी साकार नहीं होगा, क्योंकि देश और उसके लोग आपके बहकावे में आने को तैयार नहीं है। देश तोड़क गतिविधियों और राष्ट्र विरोधी आचरण की आजादी यह देश किसी को नहीं दे सकता। आप चाहे जो भी हों। जेएनयू या दिल्ली, भारत नहीं है। भारत के गांवों में जाइए और पूछिए कि आपने जो किया उसे कितने लोगों की स्वीकृति है, आपको सच पता चल जाएगा। राष्ट्र की अस्मिता और चेतना को चुनौती मत दीजिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, विचारधारा और दल इस राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता। चेत जाइए। ❑❑

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक हैं)


## :: सदस्यता संबंधी सूचना ::

अधिक जानकारी के लिए देखें : http://swadeshionline.in/

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीध्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

### सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

| स्वदेशी पत्रिका | वार्षिक | आजीवन |
|---|---|---|
| हिन्दी | 150 रुपए | 1500/– रुपए |
| अंग्रेजी | 150 रुपए | 1500/– रुपए |

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740, IFSC : BKID- 0006025 (Ramakrishnapuram) में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

# नदियां जुड़ेगी तो धारा मुड़ेगी

*जल के बगैर मनुष्य एक पल भी नहीं रह सकता। हम यह क्यों भूल रहे हैं कि पानी न होने से खेत प्यासे हैं और पलायन भी बढ़ रहा हैं। राजस्थान में इंदिरा नहर ने इलाके की तस्वीर बदल दी हैं और जहां–जहां से नहर निकली हैं, पूरा रेगिस्तानी इलाका हराभरा हो गया हैं।*

**– धर्मेन्द्र सिंह भदौरिया**

कभी नदी को मरते देखा हैं? ग्वालियर से इटावा जाते समय जब क्वारी नदी को देखा तो वह सूख गई थी। शायद वहां कुछ समय बाद बोर्ड लगा मिले कि कभी यहां क्वारी नदी थी। चंबल और यमुना में भी छोटी सी पानी की धार थी। क्या हमारी कल–कल करती सदानीरा नदियां सूख जाएंगी या फिर उन्हें जीवनदान देने के भागीरथी प्रयास 'नदी जोड़ो' योजना जल्द शुरू होगी। नदियों की धारा मुड़ेगी तो समाज और देश की धारा भी बदलेगी। खेत में अन्न बरसेगा, देश में खुशहाली आएगी।

पौराणिक कथा हैं कि राजा भागीरथ अपने पुरखों को मोक्ष दिलाने के लिए पवित्र गंगा नदी को स्वर्ग से धरती पर लेकर आए थे। गंगा से राजा भागीरथ के पूर्वजों को तो मोक्ष मिला ही, इस नदी के किनारे एक संस्कृति विकसित हुई और गंगा जहां–जहां गई, वहां पूरा इलाका ही हरा–भरा तथा धनधान्य से भरपूर हो गया। गंगा ही नहीं, अपितु सारी नदियों की यही कहानी हैं, लेकिन आज देश भर में नदियां दम तोड़ रही हैं। पेयजल और सिंचाई के पानी का संकट बढ़ने के साथ गांवों से पलायन बढ़ रहा हैं। पहले की तुलना में बारिश कम हो रही हैं। ग्लेशियरों से भी पानी नहीं मिल रहा हैं। नदियों में जो पानी आता हैं, वह समुद्र में चला जाता हैं, तो आखिर नदियां सदानीरा कैसे रहें? गंगा–जमुनी संस्कृति कैसे फले फूले? अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने तीन महती योजनाएं 'स्वर्णिम चतुर्दिक मार्ग', गांवों को सड़क से जोड़ने के लिए 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना', तथा 'नदी जोड़ो' योजनाएं शुरू की थी। दो योजनाएं तो साकार हो रही हैं, लेकिन नदी जोड़ो योजना अभी परवान नहीं चढ़ी हैं। इस योजना को लेकर तमाम किंतु–परंतु हैं। पर्यावरणविद संदेह जता रहे हैं कि इससे पारिस्थितिकीय असंतुलन पैदा होगा। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ के गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेगे। नदियां जोड़ने के लिए जो नहरें बनेंगी, उनके रास्ते में तमाम जंगल, अभ्यारण्य, गांव और खेत आएंगे। उनको उजाड़ना न पर्यावरण की दृष्टि से उचित होगा और न सामाजिक दृष्टि से।

यह चिंताएं अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन नदियों को बचाने और जल उपलब्धता सुनिश्चित करने का दूसरा कोई विकल्प भी नहीं हैं। पर्यावरणविद जो विकल्प बता रहें हैं, वह ऊंट के मुंह में जीरे समान है। पहले एक–एक गांव में दर्जनों तालाब होते थे, लेकिन अब तालाब कहां हैं? तालाब और जोहड़ों पर तो लोगों ने कब्जे कर लिए हैं। आज नहीं बल्कि अगर भविष्य में भी पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करनी हैं, तो नदियां भी जोड़नी पड़ेगी, गांव–गांव तालाब भी बनाने पड़ेगें और शहरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कड़ाई से लागू करना होगा। अब कोई भागीरथ नहीं आएंगे स्वर्ग से गंगा लाने। हमें स्वयं ही भागीरथ बनना होगा, तब हम अपना और अपनी भावी पीढ़ियों का जीवन सुनिश्चित कर पाएंगे। पानी को लेकर वैज्ञानिकों को आकलन हैं कि अगर आज नहीं चेते तो 2050 में पीने के पानी के भी लाले होंगे और दूसरी भविष्यवाणी हैं कि अगला विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। हमारे यहां तो अनेक शहरों से पानी को लेकर आपस में युद्ध जैसे समाचार आते ही रहते हैं। आबादी बढ़ रही हैं, पानी की जरूरतें बढ़ रही हैं, उपभोगवाद बढ़ रहा हैं। यहां व्यक्तिगत उदाहरण देने के लिए क्षमा चाहूंगा, लेकिन समीचीन हैं। मेरा पैतृक गांव चंबल के किनारे इटावा जिले में बरौली हैं। गांव के लोग पानी के लिए साठियां (साठ हाथ गहरे) कुंओं पर निर्भर हैं। एक–दो मीठे पानी, तो बाकी खारे पानी के हैं, लेकिन पानी का सदुपयोग कैसे होता हैं, यह मैंने अपनी दादी को करते देखा। दादी ने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था और अब तो दुनियां में नहीं हैं, लेकिन पानी को लेकर वह जितनी सजग थी, वह मुझे आज तक याद हैं। परात में बैठकर नहाते थे हम और बर्तन धोने के स्थान पर एक मटका गढ़ा था, उसमें बर्तन धोने के बाद पानी एकत्रित होता और उस पानी से दादी घर लीपतीं। नहाने के पानी को पेड़ों में डालते थे। जितना पानी पी सकते थे, उतना ही मिलता था। बर्बादी एक बूंद की भी नहीं।

**नहरें होने पर धरती की छाती को छेदकर पानी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वर्षा जल का भी इन नहरों के माध्यम से संरक्षण किया जा सकता हैं।**

जल के बगैर मनुष्य एक पल भी नहीं रह सकता। हम यह क्यों भूल रहे हैं कि पानी न होने से खेत प्यासे हैं और पलायन भी बढ़ रहा हैं। राजस्थान में इंदिरा नहर ने इलाके की तस्वीर बदल दी हैं और जहां–जहां से नहर निकली हैं, पूरा रेगिस्तानी इलाका हराभरा हो गया हैं। देश की ड़ेढ़ दर्जन नदियां जब जोड़ी जाएंगी तो इसके लिए पूरे देश में नहरों का जाल बिछ जाएगा। जरा कल्पना कीजिए यह नहरें सिर्फ पानी ही नहीं देंगी, जहां से गुजरेंगी, उस इलाके का कायाकल्प कर देंगी। आज जहां नहरें नहीं हैं, वहां लोग भूजल पर आश्रित हैं। नहरें होने पर धरती की छाती को छेदकर पानी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वर्षा जल का भी इन नहरों के माध्यम से संरक्षण किया जा सकता हैं। एक बात और कि जब कोई योजना शुरू होती हैं तो उसके फायदे भी होते हैं और नुक्सान भी। नफा–नुक्सान के लिहाज से देखेंगे तो यह योजना फायदे की ही हैं, लेकिन यह योजना जितना जल्द शुरू होगी, उतनी फायदेमंद रहेगी।

अटल बिहारी वाजपेयी दूरदृष्टा थे। अपने भाषणों में वह भी कहा करते थे, कि अगला विश्व युद्ध पानी के लिए होगा, इसलिए उन्होंने नदी जोड़ो योजना शुरू की थी, लेकिन सन् 2004 में वाजपेयी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन चुनाव हार गया और योजना ठंडे बस्ते में चली गई। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद फिर इस योजना पर काम शुरू हुआ हैं, लेकिन गति बहुत धीमी हैं, तमाम अडंगे हैं। पिछले साल मोदी सरकार ने सबसे पहले केन, बेतवा नदी जोड़ने पर काम शुरू करने का फैसला लिया था। दिसंबर 2015 में काम शुरू होना था। 7600 करोड़ रुपए की इस परियोजना से 4.46 लाख हेक्टेयर इलाके में सिंचाई होगी, लेकिन राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी अभी तक न मिल पाने के कारण यह योजना अटक गई हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में शारदा–घाघरा–गोमती को जोड़ने का काम जल्द शुरू होने जा रहा हैं। इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिंचित जमीन का रकबा बढ़ेगा। बाढ़ से तो मुक्ति मिलेगी ही, बरसाती नाले का रूप ले चुकी गोमती नदी को भी जीवनदान मिलेगा।

आज जरूरत हैं कि यह योजनाएं जल्द अमलीजामा पहनें। योजनाएं जितनी देर से शुरू होगी, परियोजना की लागत बढ़ जाएगी। यह योजना जल्द शुरू होने का मतलब हैं खुशहाली की ओर कदम बढ़ाना। अब जब कदम उठ ही गए हैं तो क्यों न तेज चलकर मंजिल पा ली जाए। ❑❑

# आरक्षण से किसको, कितना लाभ!

**इन दिनों** पूरे देश में जगह–जगह जातिगत आरक्षण की मांग को लेकर लोग आंदोलन कर रहे हैं। अभी थोड़े समय पहले ही गुजरात में आरक्षण को लेकर आंदोलन हुआ जिसमें गुजरात के साथ–साथ पूरे देश को काफी आर्थिक नुक्सान हुआ। अब हरियाणा में इसी जातिगत आरक्षण को लेकर आंदोलन हुआ जिसके कारण पूरा प्रदेश कई दिनों तक बंद रहा। इसके साथ–साथ देश में ओर भी कई स्थानों पर जातिगत आरक्षण के नाम पर कई आंदोलन हुए हैं। हरियाणा में हुए इस आंदोलन में लगभग 35000 करोड़ रूपए के नुक्सान के साथ–साथ महिलाओं की अस्मिता से खिलवाड़ के समाचारों से पूरे भारत की साख को जो नुक्सान हुआ, उसकी भरपाई करने में वर्षों लगेंगे।

आज समाचार पत्रों और इलैक्ट्रोनिक मीडिया में आरक्षण देने, न देने, जाट समुदाय का विरोध करने, न करने, इस आंदोलन में मारे गए लोगों और पीड़ितों के आश्रितों को नौकरी देने आदि मुद्दों पर चर्चा चल रही है। मगर इस समस्या के जड़ पर अर्थात जहां से इस समस्या की शुरूआत होती है उस मुद्दें पर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है या कोई ध्यान देना नहीं चाह रहा। इस विषय पर मेरे विचार में जो चल रहा है मैं वह प्रश्न आप सभी पाठकों के सामने रख रहा हूं कि क्या आरक्षण के नाम पर उठी इस आग का उपरोक्त में से कोई स्थाई समाधान है क्योंकि आरक्षण की मांग तो बढ़ रही बेरोजगारी से पैदा हो रही समस्याओं में से एक है और आरक्षण से बेरोजगारी कम नहीं हो रही, बल्कि कम हो रहे रोजगार का बंटवारा हो रहा है। बंटवारा के कारण ही देश सैकड़ों वर्षों तक गुलाम रहा और कहीं ऐसा तो नहीं की कहीं अनजाने में भारतीय आरक्षण नहीं, दोबारा देश की गुलामी मांग रहे हों? कभी इस बात पर कोई चर्चा क्यों नहीं होती कि यह समस्या पैदा ही क्यों हो रही है।

*बंटवारा के कारण ही देश सैकड़ों वर्षों तक गुलाम रहा और कहीं ऐसा तो नहीं की कहीं अनजाने में भारतीय आरक्षण नहीं, दोबारा देश की गुलामी मांग रहे हों?*
**– मनोज भारत**

देश में दिन प्रति दिन बढ़ रही बेरोजगारी के कारण देश में आरक्षण, लूटपाट, चोरी, भूखमरी आदि अनेक समस्याएं पैदा हो रही हैं। बहुत से भारतीय मानते हैं कि भारत में बढ़ रही जनसंख्या इन समस्याओं का कारण है, मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि बढ़ रही जनसंख्या केवल इंसानों की गिनती ही नहीं देश में उपभोक्ता भी बढ़ाती है। उन बढ़ रहे उपभोक्ताओं को अपने जीवनयापन के लिए बहुत से उत्पादों की भी आवश्यकता होती है जोकि अपने आप में ही रोजगार सर्जन करते हैं और जनसंख्या की वजह से अनाज की कमी को भी बहुत से बुद्धिजीवियों ने नकारा है। मेरे इस विचार का अर्थ यह नहीं है कि मैं जनसंख्या बढ़ोत्तरी का पक्षधर हूं, परंतु जनसंख्या वृद्धि को मैं बेरोजगारी का कारण नहीं समझता।

भारत में उच्च पदों पर बैठे ज्यादातर लोगों का यह मानना है कि बड़ी–बड़ी कंपनियां ही भारत में नौकरियां पैदा कर सकती हैं जोकि बेरोजगारी का समाधान हैं। यह

बात सर्वव्यापक है कि बड़ी–बड़ी कंपनियों का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना होता है, न कि समाज सेवा करना। जिसके लिए वह अपने क्षेत्र के छोटे–छोटे उद्योगों को अपने रास्ते से हटाते हुए एकाधिकार स्थापित करने की दौड़ में लगी रहती हैं। मेरा मानना है कि बड़ी–बड़ी कंपनियों के विकास का अर्थ है धन का केंद्रीकरण होना। जिससे देश का तथाकथित विकास होता तो दिखाया जा सकता है परंतु देशवासियों का विकास कहीं नजर नहीं आता। अगर आज की व्यवस्था के अनुसार कंपनियां आबाद और जनता बर्बाद होती रही तो समाज में फैल रही उपरोक्त समस्याओं को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। कंपनियों में बढ़ रहे मुनाफे को पूरी जनसंख्या में बांटकर प्रतिव्यक्ति आय को कागजों में तो बढ़ाया जा सकता है और विकास का ढौल बजाया जा सकता है। धन के हो रहे केंद्रीयकरण का प्रमाण अभी कुछ ही समय पहले समाचार पत्रों में छपे एक समाचार में देखने को मिलता है जिसमें लिखा था कि विश्व की आधी संपत्ति केवल 85 लोगों के पास है।

बड़ी–बड़ी विदेशी कंपनियां भारत को बहुत बड़ा बाजार मानती हैं और भारत के तथाकथित विकास के पक्षधर उन विदेशी कंपनियों को भारत में लाकर मुनाफे के नाम पर की जा रही लूट में भारतीयों को नौकरी देकर शामिल करना चाहते हैं। भारत की आधुनिक शिक्षा व्यवस्था जो बचपन से ही नौकरी करने के लिए तैयार करती है, चाहे वह चिकित्सा के क्षेत्र में हो, या फिर विज्ञान के क्षेत्र में। वह शिक्षा प्राप्त कर भारतीय लोग कंपनियों द्वारा की जा रही भारत की इस लूट में अनजाने में शामिल हो जाते हैं। एक अज्ञानी यात्री किश्ती में जा रहा था तो किश्ती में छेद हो गया और सभी यात्रियों में भगदड़ मच गई। लोगों ने अज्ञानी को कहा कि किश्ती में छेद हो गया है और किश्ती डूब रही है तो उन्होंने कहा कि किश्ती कल डूबती है तो आज डूब जाए यह कौन सा उसके बाप की है। जबकि वह अज्ञानी यह नहीं समझता की अगर किश्ती डूबती है तो वह भी साथ डूब जाएगा। इसी प्रकार अनजाने में भारत की इस लूट में शामिल लोग अपनी नौकरी पाने के विकास को देश का विकास मानते हैं जबकि वह यह नहीं जानते हैं कि उनका यह विकास देश का विनाश है क्योंकि बड़ी–बड़ी कंपनियां उन्हें अपना देश बेचने का वेतन देती है और अगर देश का विनाश होगा तो उनका विकास कैसे हो सकता है।

देश में भारतीयों का विकास कैसे किया जा सकता है इस बात पर गहराई और गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। अंग्रेजों की गुलामी से पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और विश्व में भारत से बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादों का निर्यात किया जाता है। इन उत्पादों को बड़े–बड़े कारखानों में नहीं बनाया जाता था बल्कि बहुत ही छोटे स्तर के कारखानों में घर–घर में बनाया जाता था जिससे प्रत्येक भारतीय का विकास होता था। भारत में हर व्यक्ति किसी न किसी कार्य में सक्षम था उसे अपनी आजीविका चलाने के लिए नौकरी की आवश्यकता नहीं होती थी। भारत के उस विकास को समझने के लिए गुलामी से पहले के भारत की सामाजिक व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था को गहराई से समझना होगा ताकि भारतीय समाज में फैल रही सभी समस्याओं को जड़ से समाप्त किया जा सके।

आज हर व्यक्ति को जीवन में उपयोग होने वाली हर छोटी से छोटी वस्तु के उत्पादन का ज्ञान ब्रह्मबिद्या हो गया है जबकि गुलामी से पहले भारत में हर प्रकार की वस्तु का उत्पादन घरों में हो जाया करता था लेकिन आज जब घरों में उत्पादन की बात करते हैं तो लोगों को विश्वास ही नहीं होता। जो तथाकथित शिक्षा भारत में दी जा रही है विद्यार्थी उस शिक्षा के नंबरों के खेल में इतना उलझा रहता है कि वह अपने पैतृक कार्य से दूर हो जाता है। वहीं दूसरी ओर तथाकथित आधुनिक शिक्षा विद्यार्थियों को नंबरों से जड़ा हुआ एक प्रमाण पत्र देती है। परंतु बड़े दुख की बात है कि लाखों रूपए और उससे भी कीमती अपने जीवन के कई वर्ष लगाकर शिक्षा के नाम पर प्रमाण पत्रों को जुटाने वाला विद्यार्थी बिना प्रमाण पत्रों के घरों को निर्माण करने वाले मिस्त्री के बराबर भी नहीं कमा पाता क्योंकि अक्षरज्ञान से महरूम रहे उस मिस्त्री ने आजीविका का ज्ञान प्राप्त किया है। भारतीय शिक्षा पद्धति द्वारा विद्यार्थियों को हुनरमंद बनाया जाता था ताकि उनकों रोजगार उनके आस–पास के परिवेश से बिना प्राकृति को नुक्सान पहुंचाए प्राप्त हो सके। आज इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए उसी भारतीय शिक्षा पद्धति की आवश्यकता है।

पाठकों को यह जानकर हर्ष होगा कि गुलामी से पूर्व की हमारी प्राचीन भारतीय जीवन व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था जीवन्त हो रही है। अभी हालही में अहमदाबाद के हेमचन्द्रा संस्कृत पाठशाला में भारत के 500 शिक्षाविदों में भारत की गुरूकुल शिक्षा पद्धति और जीवन व्यवस्था पर गहराई से चर्चा हुई। प्रत्येक भारतीय को अक्षर ज्ञान के साथ–साथ हुनरमंद बनाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत में कई जगहों पर इस प्रकार के गुरूकुल कार्य कर रहे हैं जिनमें हेमचन्द्रा संस्कृत पाठशाला और उत्तराखण्ड की मसूरी में स्थित सिद्ध नामक संस्था द्वारा चलाया जा रहा गुरूकुल भी शामिल है। इस भारतीय जीवन व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था के बारे में इतिहासकार धर्मपाल जी के साहित्य और रविंद्र शर्मा जी के व्याख्यान सौशल मीडिया में काफी सांझा किए जा रहे है। ❑❑

## 4700 करोड़ रु. में होवित्जर तोपें खरीदेगा भारत

बीएई सिस्टम्स ने 145 एम777 होवित्जर तोपों की आपूर्ति के लिए करीब 70 करोड़ डॉलर के सौदे के लिए अपने भागीदार के तौर पर महिंद्रा का चुनाव किया है। होवित्जर बेहद हल्की तोप है, जिसकी मारक क्षमता 25 किलोमीटर तक है। रक्षा सूत्रों ने बताया कि तोप सौदा विदेशी सैन्य बिक्री (एफएमएस) के जरिए होगा, लेकिन कल–पुर्जा, मरम्मत और गोला–बारूद का परिचालन भारतीय प्रणाली के जरिए होगा।

## 'कृषि उन्नति मेला'

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दिल्ली में 19 मार्च को तीन दिवसीय 'कृषि उन्नति मेला' का उद्घाटन करेंगे। इस मेले में आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियों एवं सरकार की नयी पहल का प्रदर्शन किया जाएगा। मेले में देशभर से एक लाख से अधिक किसान हिस्सा ले रहे हैं। इस मेले का आयोजन दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूसा परिसर में किया जाएगा। यहां फसल की नयी किस्मों का खेत में प्रदर्शन किया जाएगा और साथ ही आधुनिक प्रौद्योगिकियां भी प्रदर्शित की जाएंगी। इस मेले में सरकारी एवं निजी कंपनियां 600 स्टॉल

लगाएंगी। मेले में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना और जैविक खेती आदि पर किसानों को शिक्षित किया जाएगा।

## कोच गाईडेंस बोर्ड करेंगे यात्रियों की मदद

उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) जोन के इलाहाबाद, झांसी और आगरा मंडल के विभिन्न रेलवे स्टेशनों के 200 प्लेटफार्म

पर कोच गाइडेंस बोर्ड लगाने का रास्ता साफ हो गया है। इसमें बी कैटेगरी के भी स्टेशन शामिल है। इससे यात्रियों को ट्रेन आने के पहले ही जानकारी हो जाएगी कि उनका कोच प्लेटफार्म के किस स्थान पर आएगा।

एनसीआर जोन के ए वन ग्रेड के सभी और ए ग्रेड के कुछ स्टेशनों पर ही अभी कोच गाइडेंस बोर्ड लगे हुए हैं। इसकी मदद से यात्रियों को प्लेटफार्म पर आने वाली ट्रेन के कोचों की स्थिति पहले से ही मालूम पड़ जाती है और यात्री संबंधित कोच में आसानी से चढ़ जाते हैं। बड़े स्टेशनों के मुसाफिरों को यह सुविधा काफी पहले से ही मिल रही है, लेकिन छोटे स्टेशनों के यात्री इस सुविधा से अब तक वंचित है। अभी एनसीआर के विभिन्न स्टेशनों के 200 प्लेटफार्म पर इस तरह के बोर्ड लगाए जाएंगे। इन स्टेशनों में ललितपुर, बांदा, उरई, अतर्रा, डबरा, फतेहपुर, शिकोहाबाद, हाथरस, विंध्याचल, चुनार, भरवारी, कोसी, धौलपुर, खजुराहो, मानिकपुर, चित्रकूट धाम कर्वी आदि स्टेशन शामिल है।

## सस्ते पंखे देगी सरकार

बिजली की कम खपत के उद्देश्य से एलईडी बल्ब की तरह सरकार अब कम बिजली खर्च करने वाले पंखों का भी वितरण करेगी। पंखों के वितरण का यह काम आगामी अप्रैल से शुरू होगा और मात्र 60 रुपये देकर कोई भी व्यक्ति पंखे की खरीदारी कर पाएगा।

बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के माध्यम से पंखों का वितरण किया जाएगा। फिलहाल 3–4 करोड़ पंखों का वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है। एलईडी की तरह राज्य सरकार पंखों की खरीदारी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) से करेगी और फिर राज्यों की डिस्कॉम के माध्यम से उपभोक्ता पंखों की खरीदारी कर पाएंगे। बिजली, कोयला नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि एलईडी के बाद उन्होंने बिजली की कम खपत करने वाले पंखों का वितरण करने की योजना बनाई है जिसे जल्द शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पंखे की कीमत उपभोक्ता किस्तों में चुका सकते हैं। मात्र 60 रुपये देकर उपभोक्ता पंखा ले पाएगा और बाकी की रकम का भुगतान करने के लिए उसे दो साल दिए जाएंगे।

## फ्रीडम 251 मोबाईल पर संकट

मात्र 251 रुपये में स्मार्टफोन बेचने का दावा करने वाली कंपनी रिंगिंग बेल्स ने एडकॉम से 3600 रुपये प्रति फोन की दर से फोन की खरीदारी की थी। इस बात का खुलासा एडकॉम ने

किया है। एडकॉम ने कहा है कि अगर रिंगिंग बेल्स की हरकतों से उनके ब्रांड पर कोई असर पड़ता है तो वह रिंगिंग बेल्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। रिंगिंग बेल्स ने अपने 251 रुपये के स्मार्टफोन के लांच के दिन जिस फोन को दिखाया था उस फोन पर एडकॉम लिखा हुआ था। एडकॉम का फोन भारत में पहले से ही 3999 रुपये में मौजूद है। रिंगिंग बेल्स पर संचार मंत्रालय की भी नजर है। रिंगिंग बेल्स ने कहा था कि वह नोएडा व उत्तराखंड में अपना यूनिट लगाएगी जहां फोन का निर्माण किया जाएगा। मात्र 251 रुपये में फोन बेचने की घोषणा के बाद मात्र दो दिनों में 6 करोड़ से अधिक लोगों ने फोन खरीदने के लिए अपना पंजीयन करा लिया था।

## ईमेल के आविष्कारक का निधन

ईमेल का आविष्कार करने वाले अमेरिकी प्रोग्रामर रे–टॉमिल्सन का निधन हो गया, वे 74 वर्ष के थे। 1971 में टॉमिल्सन ने किसी एक नेटवर्क पर विभिन्न मशीनों के बीच सीधे इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजने का आविष्कार किया था। उससे पहले, प्रयोगकर्ता एक ही कम्प्यूटर

का इस्तेमाल करते हुए दूसरों के लिए संदेश लिख सकते थे।

## रेलवे ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए बनाई SPV

बुलेट ट्रेन शुरू करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए रेलवे ने मुंबई और अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड ट्रेन परियोजना के क्रियान्वयन के लिए एक विशेष कंपनी (एसपीवी) स्थापित की है। रेलवे ने इस नई कंपनी का नाम 'नेशनल

हाई स्पीड रेल कारपोरेशन लिमिटेड' रखा है। बुलेट ट्रेन से मुंबई और अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर की दूरी करीब दो घंटे में पूरी होने की संभावना है। इस ट्रेन की अधिकतम गति 350 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। वर्तमान में, दूरंतो इन दो शहरों की दूरी करीब सात घंटे में पूरी करती है। इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 97,636 करोड़ रुपये है और इसके 81 प्रतिशत हिस्से का वित्त पोषण जापान से ऋण के रूप में किया जाएगा।

## 7वें वेतन आयोग के लिए 70 हजार करोड़ रू.

7वें वेतन आयोग के लिए बजट में 70 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह जानकारी फाइनेंस मिनिस्ट्री के एक टॉप ऑफिशियल की ओर से दी गई है। हालांकि 7वें वेतन आयोग से सरकार पर टोटल कितना दबाव बढ़ेगा, इस पर सेक्रीटरीज की कमिटी की फाइनल रिपोर्ट आनी है। रिपोर्ट आने के बाद यह आवंटन और बढ़ाया जाएगा। अधिकारी के अनुसार यह कुल खर्च का 60 से 70 फीसदी तक है। यह राशि अलग अलग मिनिस्ट्रीज को दी जाएगी। अगर 7वां वेतन आयोग लागू होता है तो इससे 47 लाख कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा।

## सरकार को 12,400 करोड़ की चपत

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के दावे के मुताबिक टेलिकॉम सेक्टर की कंपनियां रिलायंस कम्यूनिकेशंस, टाटा, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और एयरसेल ने 46,000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा के अपने कुल रेवेन्यू को कथित तौर पर कमतर करके बताया है। CAG का कहना है कि यह हिसाब वित्तीय वर्ष 2006–07 और 2009–10 के वित्तीय वर्ष के बीच का है और इन कंपनियों ने सरकार को उसकी कमाई का हिस्सा नहीं दिया है जो अनुमान के मुताबिक 12,400 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का है।

2जी स्पेक्ट्रम पर अपने पिछले रिपोर्ट के उलट CAG ने इस बार इन टेलिकॉम कंपनियों की वास्तविक कमाई और इनके बही–खातों का मुआयना करने के बाद यह हिसाब लगाया है। 2जी केस में CAG ने सरकारी नीतियों में खामियों की वजह से अनुमानित घाटे का हिसाब लगाया था।

## नेशनल हाइवे पर रेस्त्रां एवं शॉपस

सभी नेशनल हाइवे पर हर 25 किलोमीटर की दूरी पर यूटीलिटी शॉप्स,

वाशरूम, पीने के पानी के साथ–साथ पार्किंग की सुविधा बनाई जाएंगी, जबकि 50 किलोमीटर की दूरी पर रेस्त्रां बनाए जाएंगे। इससे जहां हाइवे पर सफर करने वालों को सुविधा होगी, वहीं कारोबार के नए मौके भी मिलेंगे। इसकी वजह यह है कि ये शॉप्स और रेस्त्रां पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड पर खोले जाएंगे। एनएचएआई के पॉलिसी नोट के मुताबिक यदि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के पास एनएचएआई से सटी जमीन है और वे–साइड एमेनिटीज डेवलप करना चाहता है तो एनएचएआई की ओर से स्टैंडर्ड डिजाइन, ले–आउट जैसा सहयोग प्रदान किया जाएगा। बशर्ते, हाइवे पर आसपास 20 किलोमीटर के दायरे में से पहले से कोई वे–साइड एमेनिटीज न हो। इसके लिए एनएचएआई ने दो विकल्प दिए हैं। या तो जमीन मालिक एनएचएआई द्वारा निर्धारित लाइसेंस फीस देकर खुद ही रेस्त्रां या अन्य सुविधाएं उपलब्ध करा सकता है या जमीन मालिक एनएचएआई को रिवेन्यू शेयर मॉडल पर जमीन को लीज पर दे दे। जहां जमीन उपलब्ध नहीं है, उस इलाके में एनएचएआई द्वारा जमीन एक्वायर की जाएगी। डिटेल प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट तैयार करके यह जमीन पीपीपी मोड पर प्राइवेट कंपनियों को दी जाएगी।

## 1000 करोड़ का फर्जीवाड़ा

सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन (सीबीआई) ने सरकारी बैंक सिंडिकेट बैंक में 1,000 करोड़ रुपये के कथित फर्जीवाड़े की जांच शुरू कर दी है। सीबीआई प्रवक्ता देवप्रीत सिंह ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि जांच के सिलसिले में एजेंसी 10 जगहों की तलाशी ले रही है जिनमें बैंक की शाखाएं और कर्मचारियों के आवास शामिल हैं। सिंह ने कहा कि कथित

फर्जीवाड़े में फर्जी बिल का इस्तेमाल करने और फर्जी जीवन बीमा पॉलिसियों को लेकर ओवरड्राफ्ट लिमिट्स देने के मामले शामिल हैं। सिंडिकेट बैंक ने इस संबंध में तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की।

## महिलाएं सास को साथ ला सकेगी ऑफिस

महिलाओं को कंपनी में बनाए रखने के लिए कंपनियां तमाम तरह के प्रयासों में जुटी हैं। भारत में कई दिग्गज कंपनियां वर्किंग महिलाओं को ऑफिस में सास को लाने, बिजनस ट्रिप पर बच्चों को भी ले जाने और लंबी मैटरनिटी लीव जैसी सुविधाएं देने पर विचार कर रही हैं। इसके अलावा सब्सिडी पर डे केयर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी विचार चल रहा है। खासतौर पर मल्टीनैशनल कंपनियां और टेक फर्म इन प्रस्तावों पर विचार कर रही हैं।

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक शादी और बच्चों के बाद महिलाओं के ऑफिस छोड़ने का चलन देखने में आया है, ऐसे में उन्हें कंपनी में बनाए रखने के लिए इस तरह के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा भारत सरकार भी महिलाओं की पेड मैटरनिटी

लीव साढ़े छह महीने तक करने की तैयारी में दिख रही है। यह दुनिया में सबसे लंबी मैटरनिटी लीव में से एक होगी। माना जाता है कि वर्किंग महिलाओं पर सास की ओर से घर की देखभाल करने का दबाव रहता है। ऐसे में मेडिकल उपकरण बनाने वाली कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने महिलाओं को सास के साथ ऑफिस आने की सुविधा देने पर विचार कर रही है ताकि वह उनके साथ आकर देख सकें कि उनकी इंजिनियर बहू कैसे काम कर सकती है।

## सस्ती दवा परियोजना को झटका

केंद्र सरकार एक साल के अंदर देश में 3,000 नए जनऔषधि केंद्र खोलने की तैयारी में है, वहीं पहले से मौजूद कई केंद्र बंद होने के कगार पर पहुंच गए हैं। इसकी वजह इन केंद्रों पर दवाइयों की कमी और डिस्ट्रीब्यूशन भी ठीक नहीं होना है। इससे इन केंद्रों का प्रॉफिट काफी कम हो गया है। देश भर में पहले से चल रहे 137 जन औषधि केंद्रों में ज्यादातर पर दवाइयों की कमी बनी हुई है।

एनडीए सरकार ने मरीजों को सस्ती और बेहतर दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए देश भर में पहले से चल रहे जन औषधि केंद्रों को मजबूत किए जाने की बात कही थी। कुछ नए केंद्र भी खोले गए थे। अभी 20 राज्यों में 137 केंद्र चल रहे हैं। हर जन औषधि केंद्र पर केंद्र सरकार द्वारा 425 जेनेरिक दवाइयां और 250 मेडिकल डिवाइसेज सस्ते दामों पर उपलब्ध कराने की बात

कही गई थी। कहा गया था कि दवाइयों की संख्या बढ़ाकर 600 से ज्यादा की जाएगी। लेकिन एक साल के अंदर ही यह योजना दम तोड़ती नजर आ रही हैं। मेडिकल डिवाइसेज की बात तो दूर, दवाइयां भी समय से नहीं मिलतीं।

## ईपीएफ पर नहीं लगेगा टैक्स

इम्प्लाई प्रोविडेंट फंड (ईपीएफ) से विद्ड्राल पर अब टैक्स नहीं देना होगा। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में ईपीएफ पर टैक्स प्रपोजल के रोलबैक का एलान कर दिया। वित्तमंत्री ने बजट में पीएफ विड्राल की 60 फीसदी रकम (इंट्रेस्ट) पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव पेश किया था। सैलरीड क्लास समेत पूरे विपक्ष की तरफ इस प्रपोजल के कड़ा विरोध को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसमें दखल देना पड़ा।

## बैंकों के ऋण वसूलने में फिसड्डी डीआरटी

ऋण वसूली ट्रिब्यूनल (डीआरटी) ने भले ही उद्योगपति विजय माल्या पर बकाया कर्जे की वसूली को लेकर सख्ती दिखा दी हो, लेकिन इसका अब तक का रिकॉर्ड संतोषजनक नहीं है। उलटे तमाम कानूनी अधिकार देने के बावजूद पिछले तीन–चार वर्षों से बैंकों के फंसे कर्जे (एनपीए) की वसूली को लेकर डीआरटी का रिकॉर्ड फिसड्डी ही होता जा रहा है। वर्ष 2010–11 में डीआरटी में दायर मामलों में सिर्फ 21.55 फीसदी

राशि वसूलने में सफलता हासिल हुई थी। अब हालत यह है कि 10 फीसदी मामलों में भी कर्ज नहीं वसूल हो पा रहा है। वर्ष 2012–13 में डीआरटी में 24,177 मामले दर्ज किए गए थे। इनसे 3,557 करोड़ रुपये (14.71 फीसद) वसूले गए थे। इसके बाद के वर्ष में ट्रिब्यूनल के पास 45,350 मामले भेजे गए थे, जिनसे सिर्फ 4,460 करोड़ रुपये (9.83 फीसद) वसूलने में सफलता हासिल मिली है।

## ऐसे तय होता है किसे मिलेगा लोन

जीवन में हर कोई कभी न कभी लोन लेता ही है। कुछ लोगों को लोन आसानी से मिल जाता है और कुछ लोगों को खूब पापड़ बेलने के बाद भी निराशा ही हाथ लगती है। आपकी सैलरी और अन्य सभी योग्यताएं पूरी होती हैं, लेकिन फिर भी लोन मिलने में परेशानी होती है, तो समझ लीजिए कि ये सब हो रहा है CIBIL (क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड) की वजह से। अगर आपकी सिबिल रिपोर्ट अच्छी है तो आपको लोन आसानी से मिल जाएगा, लेकिन रिपोर्ट खराब होने पर आपको सिर्फ निराशा ही हाथ लगेगी।

सिबिल एक ऐसी संस्था है, जो देश के हर शख्स के लेन–देन का पूरा रिकॉर्ड रखती है। ये वो लेन–देन होते हैं जो कोई शख्स किसी वित्तीय संस्थान के साथ करता है। इसी रिकॉर्ड के हिसाब से आपकी सिबिल रिपोर्ट तय होती है। देश भर के करीब 500 सरकारी बैंक और वित्तीय संस्थान इससे जुड़े हुए हैं, जो हर ग्राहक के लेन–देन के बारे में सिबिल को बताते हैं। इनमें आपके लोन, ईएमआई, क्रेटिड कार्ड का बिल या फिर किसी लोन के लिए पूछताछ भी शामिल होती है। इन्हीं सब के आधार पर आपकी अच्छी या बुरी रिपोर्ट बनती है, जिसके आधार पर बैंक तय करते हैं कि वे आपको लोन दें या नहीं। इससे बैंकों को यह अंदाजा लगता है कि वह शख्स पैसे दे पाएगा या नहीं।

## जैविक उत्पादन पर सरकार का विशेष ध्यान

प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में सिक्किम को देश का पहला ऑर्गेनिक राज्य बताया। सिक्किम जैविक उत्पादों की मांग लगातार बढ़ी है जिससे वहां के किसानों की कमाई भी पहले से बेहतर हुई है। 2003 तीन में सिक्किम सरकार ने इस ओर कदम बढ़ाया था और अब ये राज्य जैविक उत्पाद के

मामले में देश में सबसे आगे है। केन्द्र सरकार ने इस बार के बजट में भी काफी जोर दिया है। साथ ही इसके लिए कई योजनाएं भी शुरू की गई है। ❑❑

# 'सतत् विकास' संगोष्ठी जमशेदपुर (झारखंड)

स्वदेशी जागरण मंच जमशेदपुर के द्वारा तुलसी भवन में ''सतत विकास'' पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय संगठक श्री कश्मीरी लाल ने कहा कि आज दुनियां के अंदर जो विकास का पैमाना है उसमें 4 प्रतिशत लोग दुनियां के 40 प्रतिशत संसाधनों का उपभोग कर रहा है यह समाज में असमानता का बहुत बड़ा कारण है। इस तरह के विकास से प्रकृति, संस्कृति और पर्यावरण का भारी नुकसान हो रहा है। वर्तमान दौर में विकास चाहिए और वह विकास जो इन सब में संतुलन बनाये रखे वह है ''सतत विकास की अवधारणा'', जिसकी ओर आज दुनियां भी सोच रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान विकास का मॉडल दुनियां में टिकने वाला नहीं है क्यूंकि इसकी नींव उपभोगतावादी सोच पर खडी है। आज वही बात दुनियां के लोग कह रहे हैं जिसकी और स्वदेशी जागरण मंच पहले से कहता आ रहा है। स्वदेशी जागरण मंच का मानना है कि विकास तो हो, लेकिन प्रकृति और पर्यावरण में संतुलन कायम रख कर। लोगों को ज्यादा पाने की चाह और अधिक से अधिक संसाधनों का दोहन दूनियां को विनाश की ओर धकेल रहा है। हमें इस मानसिकता से बाहर आना होगा और दुनियां को विकास पथ पर भारतीय चिंतन के साथ चलना होगा जिसमें संतुलन और सामंजस्य है तभी तेजी से विनाश की ओर बढ़ रही दुनियां को बचाया जा सकता है।

संगोष्ठी में कॉपरेटिव कॉलेज के प्रोफेसर डा0 के.के. शर्मा, एशिया के पूर्व अध्यक्ष आरके सिन्हा ने भी अपने विचार रखे। संगोष्ठी की अध्यक्षता विभाग संयोजक जेकेएम राजू ने की। विषय प्रवेश कौशल किशोर, मंच संचालन अमित मिश्र और धन्यवाद ज्ञापन राकेश पाण्डेय ने किया। ❑

# प.उत्तर प्रदेश प्रांतीय सम्मेलन, की सचित्र झलकियां

सम्मेलन में राष्ट्रीय संयोजक श्री अरूण ओझा जी प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए

सम्मेलन में उपस्थित प्रतिनिधिगण

डॉ. अश्वनी महाजन (राष्ट्रीय सहसंयोजक) प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए

जन जागरण रैली का एक दृश्य

सांस्कृतिक कार्यक्रम का एक दृश्य